मनदीप कौर, मैनेजिंग डायरेक्टर

पढ़ें भारत हर ख़बर सच के साथ

आज तक आमने-सामने

पंजाब, जम्मू-कश्मीर, दिल्ली एवं हरियाणा

Email : aajtakaamnesaamne.in@gmail.com

RNI No-Punhin2013/54688 16-31 AUGUST-2025

एस. के. सक्सैना, मुख्य संपादक

साल 2025 /संपादक एसके सक्सैना / www aajtakaamnesaamne.com /Help Line 9878552070

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात के हंसलपुर में ग्रीन मोबिलिटी पहल का उद्घाटन किया

प्रधानमंत्री ने सुजुकी के पहले मेड–इन–इंडिया बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन 'ई विटारा' का उद्घाटन किया और उसे हरी झंडी दिखाई

पंकज

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज गुजरात के हंसलपुर में ग्रीन मोबिलिटी पहल का उद्घाटन किया। हरित ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में यह एक बहुत बड़ा कदम है। इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि गणेशोत्सव के उल्लास के बीच, भारत की %मेक इन इंडिया% यात्रा में एक नया अध्याय जुड़ रहा है। उन्होंने कहा कि यह 'मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड' के साझा लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण छलांग है। श्री मोदी ने कहा कि आज से भारत में निर्मित इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्यात 100 देशों को किया जाएगा। उन्होंने देश में हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड निर्माण की शुरुआत की भी घोषणा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन भारत–जापान मैत्री को एक नया आयाम देगा। उन्होंने भारत के सभी नागरिकों, जापान और सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन

को हार्दिक बधाई दी। यह स्मरण करते हुए कि भारत की सफलता की कहानी के बीज 12–13 साल पहले बोए गए थे, श्री मोदी ने कहा कि 2012 में, उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान, हंसलपुर में मारुति सुजुकी को ज़मीन आवंटित की गई थी। उन्होंने कहा कि उस समय भी आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया का ही विजन था। उन्होंने कहा कि वे शुरुआती प्रयास, अब देश के वर्तमान संकल्पों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।स्वर्गीय श्री ओसामु सुजुकी को अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सरकार को उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित करने का गौरव प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि उन्हें मारुति सुजुकी इंडिया के लिए श्री ओसामु सुजुकी द्वारा देखे गए विजन के व्यापक विस्तार को देखकर प्रसन्नता हो रही है।

प्रधानमंत्री विकासशील भारत रोजगार योजना पोर्टल लाइव

नई दिल्ली (एजंसी)–प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपने 12वें स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में घोषित प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत पंजीकरण की सुविधा प्रदान करने वाला प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पोर्टल लाइव हो गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना नामक रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी। ?99,446 करोड़ के परिव्यय के साथ, इस योजना का उद्देश्य दो वर्षों की अवधि में देश में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियों के सृजन को प्रोत्साहित करना है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का उद्देश्य विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुए, सभी क्षेत्रों में रोजगार सृजन, रोजगार क्षमता और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देना है। इस योजना का लाभ 1 अगस्त 2025 और 31 जुलाई, 2027 के बीच सृजित नौकरियों पर लागू होगा। यह योजना नए रोज़गार के अवसर पैदा करने के लिए नव–नियोजित युवाओं को दो किस्तों में 15,000 तक और नियोक्ताओं को प्रति नए कर्मचारी 3000 प्रति माह तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान करेगी।

मुख्यमंत्री की ओर से पंजाब के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों की निगरानी के लिए उच्च-स्तरीय कमेटी का गठन

मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर राज्य में बाढ़ की स्थिति का लिया जायजा

रमन कुमार

चंडीगढ़, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज तीन वरिष्ठ अधिकारियों की एक उच्च–स्तरीय कमेटी का गठन किया है, जो राज्य के बाढ़ प्रभावित जिलों में चल रहे राहत और बचाव कार्यों की दैनिक आधार पर निगरानी करेगी।

यहां बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने के लिए एक उच्च–स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व विभाग, जल संसाधन और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों वाली यह कमेटी अमृतसर और अन्य बाढ़ प्रभावित जिलों में स्थायी रूप से तैनात रहेगी। उन्होंने डिप्टी कमिश्नरों और अन्य अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस उच्च–स्तरीय समिति के आदेशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाए

ताकि बाढ़ पीड़ितों को अत्यंत आवश्यक राहत प्रदान की जा सके। भगवंत सिंह मान ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि राज्य सरकार लोगों को इस संकट से निकालने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और इस नेक कार्य के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर बचाव और राहत कार्यों को और प्रभावी ढंग से सुनिश्चित करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव को बाढ़ प्रभावित जिलों का दौरा करना चाहिए और लोगों की सहायता के लिए सरकारी तंत्र को पूरी तरह से झोंक देना चाहिए। भगवंत सिंह मान ने कहा कि राहत कार्यों में व्यापक स्तर पर तेजी लाने का एकमात्र उद्देश्य लोगों को अधिकतम राहत प्रदान करना होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहाड़ी राज्यों से नदियों में जलस्तर बढ़ने से राज्य में स्थिति गंभीर हो गई है। उन्होंने कहा कि आज तक रावी नदी में 14.11 लाख क्यूसेक पानी आया है, जो अब तक इस नदी में सबसे अधिक है। यहां तक कि जब 1988 में राज्य में सबसे भयानक बाढ़ आई थी, तब भी इस नदी में 11.20 लाख क्यूसेक पानी आया था। भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार ने नदियों से अधिकतम पानी निकालने के लिए हरियाणा और राजस्थान को पहले ही पत्र लिखकर भेज दिया है।

उद्योगपतियों से सुझाव लेने और समस्याएँ सुलझाने के लिए अमृतसर से उद्योग मंत्री ने शुरू की "राइजिंग पंजाब" पहल

अब हमारे निवेशकों को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, हम खुद उनके पास जाएंगे – अरोड़ा

एसके सक्सैना

चंडीगढ़/अमृतसर, 19 अगस्त: मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान के औद्योगिक क्रांतिकारी विज़न के तहत पंजाब में उद्योग को बड़ा प्रोत्साहन देने के लिए आज उद्योग एवं बिजली मंत्री श्री संजीव अरोड़ा ने माझा क्षेत्र के उद्योगपतियों से, जिनमें अमृतसर के अलावा गुरदासपुर, तरनतारन, बटाला और पठानकोट के उद्योगपति शामिल थे, औद्योगिक नीति के लिए सुझाव लेने और उनकी समस्याएँ सुलझाने के उद्देश्य से गुरु की नगरी अमृतसर से 卐राइजिंग पंजाब – सुझाव से समाधान तक卐 की शुरुआत की। इस अवसर पर आए उद्योगपतियों का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब के सभी बड़े शहरों में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और आज यह पहला विशेष आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य नई उद्योग–अनुकूल नीतियों के बारे में जागरूकता फैलाना, नए निवेश के लिए माहौल तैयार करना और सरकार–उद्योग जगत के बीच सीधा संवाद कायम करना है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह पहल पंजाब में नए निवेश,

अधिक रोजगार और लोगों की खुशहाली के नए दरवाज़े खोलेगी। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सुझाव से समाधान तक पहुँचना ही हमारी ज़िम्मेदारी है। उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मैं बातों में नहीं, काम में विश्वास रखता हूँ। उन्होंने कहा कि उद्योगपतियों के सुझाव मैंने नोट कर लिए हैं और जो भी काम होने वाले हैं, वे कुछ ही दिनों में पूरे होंगे। उन्होंने कहा कि अमृतसर गुरु नगरी है, पंजाब का प्रवेश द्वार है और यह दुनिया का सबसे सुंदर शहर बनेगा। अमृतसर की मेहमाननवाज़ी की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की अपार संभावनाएँ हैं और सरकार उसके लिए काम करेगी। कैबिनेट मंत्री ने पंजाब राज्य इंडस्ट्री एंड एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन द्वारा बीते समय में जारी पाँच अलग–अलग नोटिफिकेशनों का ज़िक्र करते हुए कहा कि ऐसी योजनाएँ किसी भी राज्य सरकार ने नहीं दीं, जैसी हमारी सरकार ने उद्योगपतियों के लिए लागू की हैं।

वड़िंग ने डेरा बाबा नानक में व्यापारी की हत्या की निंदा की

एसके सक्सैना

चंडीगढ़, 20 अगस्त- पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने गुरदासपुर के डेरा बाबा नानक में बीती रात एक व्यापारी रवि ढिल्लों की नृशंस हत्या की निंदा की है। जिस संबंध में बताया जा रहा है कि उनके द्वारा फिरौती के पैसे देने से इनकार करने पर कथित रूप से कुछ गैंगस्टरों के इशारे पर यह हत्या करवाई गई है। वड़िंग ने बीती शाम जालंधर में एक डॉक्टर राहुल सूद पर हुए हमले की भी निंदा की है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि पंजाब में भय और दहशत का माहौल है और फिरौती के लिए हत्याएँ नया सामान्य दौर बन गई हैं। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में लोगों की जान–माल की रक्षा करने में पूरी तरह विफल रही है और कोई भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। इस बीच, राज्य में बिगड़ती कानून–व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि अपराधियों को कानून का कोई डर नहीं है। ऐसा लगता है कि राज्य सरकार शासन करने की इच्छा छोड़कर अन्य कामों में व्यस्त है, जबकि अपराधी और गैंगस्टर राज कर रहे हैं। उन्होंने ज़ोर देते हुए कहा कि पुलिस पिछली घटनाओं में दोषियों को गिरफ्तार करके कोई कार्रवाई करने में विफल रही है। ऐसे में अपराधियों के हौसले दिन–ब–दिन बुलंद होते जा रहे हैं।

कहा- पंजाब में फिरौती के लिए हत्याएँ अब नया सामान्य दौर बन गई हैं

यहाँ तक कि पुलिस को गैंगस्टरों द्वारा पहले की गई हत्याओं और जानलेवा हमलों की भी कोई

जानकारी नहीं है। जिस पर वड़िंग ने चेतावनी दी है कि व्यापारियों, कारोबारियों और डॉक्टरों जैसे लोगों की हत्या और उन्हें डराने–धमकाने का यह चलन राज्य में पूरी तरह से आर्थिक तबाही ला देगा, क्योंकि लोग अब यहाँ सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। इसके अलावा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने पटियाला के तलवंडी साबो के कांग्रेस कार्यकर्ता दिलावर सिंह पर हुए जानलेवा हमले की भी निंदा की है।

पूर्व सांसद सुशील रिंकू ने सुल्तानपुर लोधी के बाढ़ प्रभावित गांवों का जायजा लिया

बाढ़ प्रभावित इलाको के लोगों को सुविधा देने में फेल हुई पंजाब सरकार –सुशील रिंकू

सुभाष चंद्र

जालंधर, 19 अगस्त 2025। पंजाब भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद सुशील रिंकू और पूर्व सीपी एस केडी भंडारी ने आज जालंधर जिले के सुल्तानपुर लोधी में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाके के लोगों को भोजन सामग्री, दवाइयाँ और अन्य जरूरी सामान वितरित किया। सुशील रिंकू ने सतलुज दरिया के साथ लगते कमेवाल और बागूपुर गांवों का दौरा कर वहां के लोगों से बातचीत की। बातचीत में गांवों के लोगों ने बताया कि पंजाब सरकार की तरफ से उन्हें कोई मदद नहीं मिल रही है, न ही कोई प्रशासनिक अधिकारी उनके गांव में आया है। पूर्व सांसद सुशील रिंकू ने मौके पर पहुंच कर हर तरह की मदद करने का आश्वासन दिया और प्रशासनिक अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। रिंकू ने अधिकारियों से लोगों को हर तरह की सुविधा प्रदान करने के लिए कहा। सुशील रिंकू ने कहा कि बाढ़ प्रभावित इलाके के लोगों को जरूरी सामान जैसे पानी, राशन, जानवरों के लिए चारा आदि जरूरी सामान मुहैया करवाया जाय। इस मौके पर पर उनके साथ हरदीप राणा, हरजिंदर सिंह ठेकेदार, विक्की गुजराल, अश्वनी तुली, सनी बैंस, सरबजीत सिंह देयोल, बलवंत सिंह आदि लोग शामिल थे।

युद्ध नशों विरुद्ध'-पंजाब पुलिस द्वारा राज्य भर में कासो के दौरान 272 नशों के हॉटस्पॉटस पर छापेमारी

रमन कुमार

चंडीगढ़, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दिशा–निर्देशों के अनुसार पंजाब में से नशों के मुकम्मल ख़ात्मे के लिए अथक यत्नों में नशा विरोधी मुहिम के 170 वें दिन, पंजाब पुलिस ने आज राज्य भर में पहचाने गए ड्रग हॉटस्पॉटस – नशों और मादक पदार्थों की बिक्री वाले स्थानों – पर एक राज्यव्यापी घेराबन्दी और खोज मुहिम (कासो) चलाई। पुलिस डायरैक्टर जनरल (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव के निर्देशों पर राज्य के सभी 28 पुलिस जिलों में एक ही समय कासो मुहिम चलाई गई। बताने योग्य है कि दिन भर चले इस आपरेशन के दौरान पुलिस टीमों ने राज्य भर में नशीले पदार्थों सम्बन्धी

196 नशा तस्कर 2.4 किलोग्राम हेरोइन और 2 किलोग्राम अफ़ीम सहित काबू

272 हॉटस्पॉटसों पर छापेमारी की, जिसमें 164 ऐफआईआरज़ दर्ज करने के बाद 196 व्यक्तियों को गिरफ़्तार किया गया है। पुलिस टीमों ने गिरफ़्तार किये गए नशा तस्करों के कब्ज़े में से 2.4 किलोग्राम हेरोइन, 2 किलोग्राम अफ़ीम, 30 किलोग्राम गाँजा, 13,451 नशीली गोलियां/ कैपसूल और 15, 020 रुपए की ड्रग मनी भी बरामद की है।

पंजाब स्कूलों में उद्यमिता को मुख्य विषय के रूप में शामिल करने वाला पहला राज्य बना

शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस और 'आप' के पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया द्वारा पाठ्यक्रम लॉन्च

पंकज कुमार

चंडीगढ़, पंजाब देश का पहला राज्य बन गया है जिसने कक्षा 11 के छात्रों के लिए 'उद्यमिता' को मुख्य विषय के रूप में पेश किया है। उद्यमिता को मुख्य विषय बनाने का उद्देश्य छात्रों में उद्यमशील मानसिकता को प्रोत्साहित करना है ताकि वे नौकरी खोजने वालों के बजाय रोजगार सृजन करने वाले बन सकें। शैक्षणिक सत्र 2025–26 से शुरू होने वाली इस महत्वपूर्ण पहल की आज पंजाब के स्कूल शिक्षा मंत्री श्री हरजोत सिंह बैंस और 'आप' के पंजाब प्रभारी श्री मनीष सिसोदिया ने शुरुआत की। यहाँ म्युनिसिपल भवन में आयोजित लॉन्च समारोह को संबोधित करते हुए श्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि पंजाब देश का पहला राज्य है जिसने स्कूल शिक्षा में उद्यमिता को औपचारिक रूप से एक मुख्य विषय के रूप में शामिल किया है। उन्होंने कहा कि इससे छात्रों को नवाचारी, समस्या समाधानकर्ता और रोजगार सृजनकर्ता बनाया जा सकेगा। नए लॉन्च किए गए विषय की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए शिक्षा मंत्री ने बताया कि यह पाठ्यक्रम अनुभव और व्यावहारिक शिक्षा पर आधारित है। इसके अंतर्गत छात्र टीमें बनाएंगे, व्यावसायिक विचार विकसित करेंगे, प्रोटोटाइप बनाएंगे, सीड फंडिंग की तैयारी करेंगे और बाज़ार में अपने उत्पादों/सेवाओं को लॉन्च करेंगे। उन्होंने आगे बताया कि इसमें छात्रों पर परीक्षा का कोई बोझ नहीं होगा,

लिखित परीक्षाओं की बजाय स्कूल–आधारित मूल्यांकन होगा। मूल्यांकन में आत्म–मूल्यांकन, साथियों द्वारा मूल्यांकन और शिक्षक/मेंटॉर द्वारा मूल्यांकन शामिल होंगे, जो सीखने के अनुकूल माहौल को बढ़ावा देंगे। उन्होंने बताया कि इस विषय के सालाना 18 पीरियड (3 थ्योरी और 15 प्रोजेक्ट आधारित) होंगे, जिससे यह पाठ्यक्रम छात्रों पर बिना अतिरिक्त बोझ डाले रोचक शिक्षा सुनिश्चित करेगा। इस पहल के आर्थिक प्रभाव को रेखांकित करते हुए श्री बैंस ने कहा कि राज्य के 3,840 सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में 2.68 लाख से अधिक छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इनमें से यदि 10 प्रतिशत सफलता दर से छात्र–आधारित आर्थिक गतिविधि से सालाना 300–400 करोड़ रुपये कमाए जा सकते हैं। यह पहल स्थानीय मांग, रोजगार और सामुदायिक भागीदारी पैदा करेगी जिससे जमीनी स्तर पर आर्थिक विकास को गति मिलेगी।

संपादकीय

उत्तर भारत बाढ़ की चपेट में – चारों ओर त्राहिमाम त्राहिमाम

कई दिनों से निरंतर बर्षा होने कारण उतर भारत के गांव, कस्बे एवं शहर बुरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। चारों ओर पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। बारिश एवं पानी की उचित निकासी न होने के कारण आना जाना अति मुश्किल हो गया है। उधर नदियों नालों दरियाओं के आस पास के इलाके बुरी तरह से बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। अभी भी डैम,नदियां नालों दरियाओं में बारिश का जल स्तर उफान मार कर खतरे की घंटी बजा रहा है। कहीं कहीं नदियों नालों नहरों का पानी किनारे तोड कर नजदीकी इलाकों में घुस गया है। यदि बात करें पंजाब की तो सूत्रोंनुसार 1018 गांव यानी कृषि क्षेत्रीय भूमि 61000 हैक्टर बुरी तरह से बाढ़ग्रस्त हुई। इन जिलों में पठानकोट 81 गांव , फाजिलका 52 गांव,तरनतारन 45 गांव ,श्री मुक्तसर साहिब 64 गांव, संगरूर 22 गांव,फिरोजपुर 101गांव ,कपूरथला 107 गांव , गुरदासपुर 323 गांव,होशियारपुर 85 गांव एवं मोगा के 35 गांव बुरी तरह से प्रभावित हैं। यदि बाढ़ग्रस्त क्षेत्रफल की बात करें तो फाजिलका 16632,फिरोजपुर 10806,कापूरथला 11620,पठानकोट 7000,तरनतारन 9928,होशियारपुर 5287 हेक्टेयर हैं। एन डी आर एफ,बी एस एफ,सेना इत्यादि द्वारा 11330 बाढ़ पीड़ितों को बचा कर सुरक्षित बचाया। अभी भी बाढ़ पीड़ितों के बचाव सहायतार्थ 77 कैंप जारी हैं। सरकार के निर्देशानुसार प्रशासन की ओर से बाढ पीड़ित परिवार की अधिक से अधिक सहायता की जा रही। धार्मिक एवं समाजिक संगठनों द्वारा भी बड़ चड कर इस संकट की घडी में जरूरतमंद परिवार को सहयोग प्रदान किया जा रहा है। आशा है कि कुछ दिनों में बारिश का पानी समान्य हो जाएगा। फिर धीरे धीरे बाढ़ पीड़ितों के जीवन में सुधार आएगा। परंतु अफसोस=बाढ़ के दौरान पशुधन गुम हुआ , बाढ़ में बह गया या मर गया, रहन बसेरे ढह गए– सिर ढकने के लिए जगह का ना रहना,पानी के दूषित होने के कारण किसी संक्रमित रोग ग्रस्त होने का खतरा, बच्चों की शिक्षा का प्रभावित होना, बच्चों एवं बूढे लोगों के स्वास्थ्य का प्रभावित होना। कारोबार फिर शून्य से प्रारंभ करना,कमाई के साधनों में कमी हो जाना, फसल का पूर्ण रूप से नष्ट होने से ऋणी होना, कृषि भूमि बुरी तरह से बाढ़ ग्रस्त होने कारण अगली फसल का उचित उत्पादन न होना इत्यादि। इस प्रकार के प्राकृतिक कहर ने मानव जीवन को झंकोड कर रख दिया। राजनीतिक दलों को इस संकट काल में एकजुट हो कर समस्या का समाधान करना चाहिए न कि एक दूसरे पर लांछन लगाना! सरकार को बाढ़ग्रस्त इलाके का सर्वेक्षण करके पीड़ित परिवारों की सहायतार्थ आर्थिक सहयोग पैकेज शीघ्र जारी करना चाहिए।

आज तक आमने सामने
RNI NO -PUNHIN0/2013/54688
Printed by Mandeep Kaur, Published by Mandeep Kaur, Owned by Mandeep Kaur & Printed at Dashmash Printers 178-179 Ranjit Nagar, Jalnadhar City, Published 87 Ranjit Nagar Near Bus Stand, Jalandhar, Punjab
Editor Surinder Kumar (SK Saxena)
Responsible for selection of News under the PRB ACT.
All Rights Reserved Reproduction in whole or in Part without Permission in Prohibited, All disputes shall be settled at Jalandhar Jurisdiction only
Faxt No. : 0181-5024001, Conact No : 0181-5077100

आवश्यक सूचना

आज तक आमने-सामने का इस समाचार पत्र में मुद्रित वज्ञिापनों (डिस्पले/क्लासीफाईड) के तथ्यों सबंधी कोई दायित्व नहीं है। महारा समाचार पत्र इनको सत्यापित नहीं करता। पाठकों से अनुरोध है कि वे इन विज्ञापनों पर कार्यवाही करने से पूर्व सभी तथ्यों की स्वयं पुष्टि कर लें। -प्रधान संपादक

मुख्य सचिव पंजाब ने पौंग डैम और मुकेरियां के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा

कहा, पंजाब सरकार बाढ़ प्रभावितों को हर संभव सहायता सुनिश्चित करवाने के लिए वचनबद्ध, सभी विभागों की टीमें 24 घंटे राहत कार्यों में तैनात

रमन

तलवाड़ा/मुकेरियां (होशियारपुर), 30 अगस्त-मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत सिंह मान के निर्देशों पर मुख्य सचिव पंजाब के.ए.पी. सिन्हा ने आज पौंग डैम और मुकेरियां के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इस मौके पर उनके साथ प्रमुख सचिव जल संसाधन विभाग कृष्ण कुमार, डिप्टी कमिश्नर आशिका जैन और एससपी संदीप कुमार मलिक भी मौजूद थे। मुख्य सचिव ने सबसे पहले पौंग डैम का निरीक्षण किया और वहां मौजूद अधिकारियों से डैम के वर्तमान जलस्तर एवं छोड़े जा रहे पानी की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि बांध में आ रहे पानी के इनफ्लो को ध्यान में रखते हुए तकनीकी मानकों के आधार पर ही डिस्चार्ज किया जाए, ताकि निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। उन्होंने अधिकारियों को लगातार सतर्क रहने और स्थिति पर चौबीसों घंटे निगरानी रखने के भी निर्देश दिए।

राहत सामग्री से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं तक- हर पल बाढ़ पीड़ितों के साथ खड़ी मान सरकार

बाढ़ पीड़ितों के दुख साझा करने के लिए पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरी सरकारी मशीनरी

सुभाष चंद्र

चंडीगढ़, पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों में पंजाब सरकार, आम लोगों और विभिन्न संस्थाओं द्वारा राहत सामग्री लगातार भेजी जा रही है। प्रभावित इलाकों के लोगों की हर तरह की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य सेवाओं पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। लोगों के सहयोग से राज्य सरकार की पूरी मशीनरी बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए दिन–रात एक कर रही है। पंजाब के कैबिनेट मंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमन अरोड़ा ने शनिवार को सुनाम से राहत सामग्री से भरे 11 ट्रक पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए रवाना किए। इन ट्रकों में बाढ़ प्रभावित परिवारों के लिए राशन किटें, खाने–पीने की वस्तुएं और पशुओं के लिए चारा समेत ज़रूरी सामान शामिल था। वहीं, पंचायत मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने फाज़ल्का ज़िले के दौरे के दूसरे दिन ज़िला प्रशासन के साथ बाढ़ राहत प्रबंधों की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा ज़िले में बाढ़ प्रभावित परिवारों को

राशन वितरण का पहला चरण पूरा कर लिया गया है और अब दूसरे चरण में फिर से प्रभावित परिवारों तक राशन किटें भेजी जाएंगी। उन्होंने बताया कि पहले चरण में 3835 परिवारों को राशन किटें वितरित की गईं और मवेशियों के लिए चारा भी उपलब्ध कराया गया। उन्होंने कहा कि राहत शिविरों में आए लोगों की हर तरह से मदद की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा पत्तन पोस्ट, कांवां वाली पत्तन और अत्तू वाला पुल पर 24 घंटे के लिए मेडिकल टीमें तैनात की गई हैं। गांवों में पीने के पानी की लगातार सैंपलिंग की जा रही है और नमूने जांच के लिए चंडीगढ़ की प्रयोगशाला भेजे जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा अब तक 1500 मरीजों की जांच कर आवश्यक दवाइयां निःशुल्क दी गई हैं, जबकि पशुपालन विभाग की 14 टीमें भी ज़िले में सक्रिय हैं।

इस अवसर पर कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने भी बारिश के बीच फाज़ल्का के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उन्होंने गांव घूरका के बाढ़ प्रभावित लोगों से बातचीत की और आश्वासन दिया कि पंजाब सरकार इस कठिन घड़ी में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है।

जेल और परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने ज़िला तरनतारन के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, स्थिति का जायज़ा लिया और राहत कार्यों का नेतृत्व किया। भुल्लर ने गांव कोट बुड्ढा, भोजोके, झुग्गियां पीर बख्श, रादलके, राम सिंह वाला, सभरा और रसूलपुर सहित धुंसी बांध से लगे कई गांवों में सूखा राशन, पीने का पानी, ज़रूरी खाद्य सामग्री और पशुओं के लिए चारा, फ़ीड तथा चोकर वितरित किया। उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया कि कोई भी परिवार राशन से वंचित नहीं रहेगा। कैबिनेट मंत्री लाल चंद कटारूचक्क और डॉ. बलबीर सिंह ने भोआ के बमियाल क्षेत्र और नरोट जैमल सिंह के बाढ़ प्रभावित विभिन्न गांवों का दौरा किया और रावी नदी का भी जायज़ा लिया। इनमें नरोट जैमल सिंह, जैदपुर, बमियाल, भगवाल, कोहलियां अड्डा आदि शामिल थे। इस अवसर पर सरना से विभिन्न क्षेत्रों के लिए राशन से भरे वाहन भी रवाना किए गए।

डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा रोज़ाना लगभग 27 मेडिकल कैंप लगाए जा रहे हैं और करीब 500–600 लोग रोज़ इन कैंपों से लाभ उठा रहे हैं।

लुधियाना में बनेगी शहीद ऊधम सिंह स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी

कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा और हरजोत बैंस ने विश्वविद्यालय प्रबंधकों को विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए आवश्यक अनुमतियों सहित हर संभव सहयोग देने का भरोसा दिया

मनदीप कौर

चंडीगढ़, शिक्षा और उद्योग की आवश्यकताओं के बीच की खाई को पाटने और प्रदेश के युवाओं को अति–आधुनिक कौशल तथा उद्यमिता की महारत से सशक्त बनाने के उद्देश्य से लुधियाना में एक विश्व–स्तरीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा, जिसका नाम महान स्वतंत्रता सेनानी शहीद ऊधम सिंह के नाम पर रखा गया है। यह गौरवपूर्ण संस्थान युवाओं में नवाचार, रचनात्मकता और आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करेगा तथा उद्योग की जरूरतों के अनुसार युवाओं को शिक्षा प्रदान करेगा, जिससे पंजाब में आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। शहीद ऊधम सिंह स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी की स्थापना संबंधी आधिकारिक घोषणा संबंधी समारोह में पंजाब के रोजगार उत्पत्ति, कौशल विकास एवं प्रशिक्षण मंत्री तथा 'आप' के प्रदेश अध्यक्ष श्री अमन अरोड़ा, तकनीकी शिक्षा एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री श्री हरजोत सिंह बैंस और 'आप' पंजाब के प्रभारी श्री मनीष सिसोदिया ने शिरकत की। शहीद ऊधम सिंह स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी लुधियाना में कम्बोज समाज द्वारा दान की गई 50 एकड़ भूमि पर स्थापित की जाएगी और इस पर 500 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है। यह विश्वविद्यालय परिसर अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे, डिजिटल कक्षाओं, शोध केंद्रों, नवाचार केंद्रों और इनक्यूबेशन सुविधाओं से लैस होगा। इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य छात्रों

को आधुनिक युग, प्रौद्योगिकी–आधारित अर्थव्यवस्था, नवाचार, उद्यमिता और उद्योग–आधारित उद्यमों को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक कौशल और संसाधन उपलब्ध कराना है। पंजाब के कैबिनेट मंत्रियों श्री अमन अरोड़ा और श्री हरजोत सिंह बैंस ने मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा युवाओं को उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप कुशल बनाने के प्रयासों पर प्रकाश डाला। उन्होंने भरोसा दिलाया कि विश्वविद्यालय प्रबंधकों को सरकार की ओर से हर संभव सहयोग तथा स्थापना और संचालन के लिए सभी आवश्यक अनुमतियों में मदद दी जाएगी। इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए श्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि शहीद ऊधम सिंह स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी कौशल विकास और आर्थिक प्रगति को प्रोत्साहित करने के लिए पंजाब सरकार के प्रयासों को मजबूती देने की दिशा में एक अहम कदम है। व्यावहारिक कौशलों और औद्योगिक साझेदारी पर ध्यान केंद्रित करके यह विश्वविद्यालय ऐसे स्नातक तैयार करेगा जो रोजगार पाने में सक्षम होंगे। श्री सिसोदिया ने विश्वविद्यालय के लिए भूमि दान करने और शिक्षा में योगदान हेतु कम्बोज समाज की प्रशंसा की। जलालाबाद से विधायक श्री जगदीप गोल्डी कम्बोज ने कहा कि शहीद ऊधम सिंह स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी लुधियाना को कौशल विकास और उद्यमिता के केंद्र में बदल देगी, जो भारत और विदेशों से छात्रों को आकर्षित करेगी। कम्बोज समाज के लिए यह परियोजना एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है जो शिक्षा, युवाओं के सशक्तिकरण और शहीद ऊधम सिंह की विरासत के सम्मान के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस अवसर पर शिक्षा, कौशल विकास और सशक्तिकरण के प्रति डॉ. संदीप सिंह कौड़ा के योगदान को मान्यता देते हुए कम्बोज समाज ने उन्हें इस विश्वविद्यालय का संस्थापक चांसलर घोषित किया। डॉ. संदीप सिंह कौड़ा ने कहा कि विश्वविद्यालय का ध्यान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, रोबोटिक्स, साइबर सुरक्षा और उन्नत उद्यमिता कार्यक्रमों जैसी अति–आधुनिक प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित होगा।

ज्वैलर हमले के पीछे गैंगस्टर लखबीर लंडा का हाथ; मुख्य शूटर गिरफ्तार

गिरफ्तार किया गया शूटर विदेश आधारित गैंगस्टर लखबीर लंडा के इशारों पर वारदातों को देता था अंजाम- डीजीपी गौरव यादव, ज्वैलर हमले से संबंधित मामले में की गई यह तीसरी गिरफ्तारी है- एडीजीपी एजीटीएफ प्रमोद बान

एस. के. सक्सैना

चंडीगढ़, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दिशा–निर्देशों के तहत पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के दौरान संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल करते हुए, पंजाब पुलिस की एंटी–गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) ने ज्वैलर हमले में शामिल मुख्य शूटर को गिरफ्तार कर लिया है। यह जानकारी आज यहां पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने दी। गिरफ्तार आरोपी की पहचान जगरोशन सिंह निवासी नौशहरा पन्नूआं, तरनतारन के रूप में हुई है। आरोपी का कोई आपराधिक पिछला रिकॉर्ड नहीं है। जानकारी के अनुसार, 14 अगस्त 2025 को शाम करीब 6 बजे जिला फिरोज़पुर के ज़ीरा में कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने एक ज्वैलरी शॉप के मालिक पर फायरिंग की थी, जिसमें दुकान मालिक गंभीर रूप से घायल हो गया था। डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि शुरुआती जांच से पता चला है कि शूटरों ने विदेश आधारित गैंगस्टर लखबीर सिंह उर्फ लंडा के इशारों पर इस वारदात को अंजाम दिया था। उन्होंने कहा कि इस मामले में आगे–पीछे के संबंध जोड़ने के लिए जांच जारी है ताकि पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया जा सके।

गुरमीत सिंह खुड्डियां ने बाढ़ से क्षतिग्रस्त लिंक सड़कों पर रिपोर्ट मांगी

मरम्मत के लिए ज़रूरी सहायता हेतु अंतिम रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी जाएगी–कृषि मंत्री

सोनू

चंडीगढ़, आगामी खरीफ खरीद सीज़न को ध्यान में रखते हुए सड़कों के संपर्क की तेज़ी से बहाली सुनिश्चित करने के लिए, पंजाब के कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने आज पंजाब मंडी बोर्ड के अधिकारियों को हाल ही में आई बाढ़ से लिंक सड़कों को हुए नुकसान पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर पेश करने के निर्देश दिए हैं। श्री खुड्डियां, जिनके साथ पंजाब मंडी बोर्ड के चेयरमैन श्री हरचंद सिंह बरसट भी मौजूद थे, ने आज यहां अपने कार्यालय में कृषि विभाग और पंजाब मंडी बोर्ड के अधिकारियों के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक के दौरान बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मंडी बोर्ड की सड़कों की स्थिति की समीक्षा की। कृषि मंत्री ने कहा कि सड़कों की बहाली के लिए आवश्यक सहायता हेतु केंद्र सरकार को जल्द ही अंतिम रिपोर्ट भेजी जाएगी। श्री खुड्डियां ने कहा कि हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसानों की उपज का हर दाना बिना किसी रुकावट और परेशानी के मंडियों तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस मंतव्य के लिये पहला काम गाँवों की लिंक सड़कों को हुए नुकसान की पूरी स्थिति का पता लगाना है ताकि बहाली का कार्य युद्ध स्तर पर शुरू किया जा सके। बैठक में बाढ़ के नुकसान के आकलन के अलावा पंजाब सरकार द्वारा लागू की जा रही

लिंक सड़क परियोजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई। लंबित कार्यों में तेजी लाने के लिए श्री खुड्डियां और श्री बरसट ने आदेश दिया कि लिंक सड़कों की मरम्मत और उन्नयन के लिए सभी आवश्यक मंजूरियां तुरंत दी जाएँ ताकि जल्द से जल्द टेंडर जारी कर कार्य शुरू किया जा सके। कृषि और किसान कल्याण विभाग के प्रबंधकीय सचिव डॉ. बसंत गर्ग ने अधिकारियों को मंडी बोर्ड की सभी चल रही विकास परियोजनाओं को तेजी से लागू करने के निर्देश देते हुए कहा कि यह कदम खासकर प्राकृतिक आपदाओं को ध्यान में रखते हुए कृषि बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और किसानों की सहायता करने के प्रति मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार की प्रतिबद्धता का हिस्सा हैं। बैठक में अन्य के अलावा पंजाब मंडी बोर्ड के सचिव श्री रामवीर, मुख्य इंजीनियर पंजाब मंडी बोर्ड गुरिंदर सिंह चीमा, मुख्य इंजीनियर पंजाब मंडी बोर्ड अमनदीप सिंह और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।

पढ़ें भारत हर ख़बर सच के साथ
आज तक आमने-सामने
पंजाब, जम्मू-कश्मीर, दिल्ली एवं हरियाणा
Email : aajtakaamnesaamne.in@gmail.com
RNI No-Punhin2013/54688

पंजाब के 12 जिले पानी में डूबे, 1044 गांव प्रभावित

अपने बच्चों पर रहम करो भगवान

स्टेट ब्यूरो

लगातार हो रही बारिश ने पंजाब और हिमाचल प्रदेश को दर्द और तबाही की गहरी अंधेरी खाई में धकेल दिया है। कहीं पहाड़ दरककर बस्तियों को निगल रहे हैं, तो कहीं बाढ़ का उफनता पानी घर–आंगन और रोजी–रोटी तक बहाकर ले गया है। हर तरफ मासूम बच्चों की चीखें, बुजुर्गों की बेबसी और मेहनतकश किसानों की टूटी उम्मीदें पसरी पड़ी हैं। जिन गांवों में कभी जीवन की रौनक और त्योहारों की गूंज सुनाई देती थी, वहां अब खामोशी, मलबा और उजाड़ ही उजाड़ है। टूटी सड़कों और डूबे खेतों के बीच, राहत शिविरों में आसरा लिए परिवार आसमान की ओर हाथ उठाकर यही पुकार रहे हैं कि 'हे परमात्मा, अब रहम करो... हमारी यह पीड़ा और मत बढ़ाओ।'

वॉटरशेड-साकार होता विकसित भारत का सपना

जल और मिट्टी संरक्षण से कृषि और किसान समृद्धि की ओर

लेखक
शिवराज सिंह चौहान

जल ही जीवन है और मिट्टी हमारा अस्तित्व, हमारा आधार है। जल और मिट्टी के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आज जब पर्यावरण संकट गहराता जा रहा है, कुएं सूख रहे हैं, नदियों की धाराएं कमजोर हो रही हैं और भूजल पाताल में समा रहा है, तब यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जल और मिट्टी की रक्षा करें। जब हमारे खेत हरे-भरे होंगे और किसान खुशहाल होंगे, तभी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत-2047 के संकल्प को साकार किया जा सकेगा, क्योंकि इस संकल्प का रास्ता हमारे गांवों की पगडंडियों, उपजाऊ मिट्टी और लहलहाती फसलों से होकर ही गुजरता है।

आज बिगड़ते पर्यावरण के कई जगहों पर भूजल का स्तर हजार-डेढ़ हजार फीट नीचे चला गया है। अगर हमारी उपजाऊ मिट्टी इसी तरह बहती रही और जमीन बंजर होती रही, तो हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य कैसा होगा? इसी दूरदर्शी सोच और भविष्य की चिंता को लेकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने एक बीड़ा उठाया है। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने हमेशा दूरदृष्टि से काम किया है। वे सिर्फ आज की नहीं, आने वाले 50-100 वर्षों की सोचते हैं। उनके नेतृत्व में भारत सरकार का भूमि संसाधन विभाग, 'प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना' के तहत 'वॉटरशेड विकास घटक (ड्ढष्टष्ट-क्करूयस्ङ्घ)' को पूरे देश में लागू कर रहा है। लेकिन यह काम अकेले सरकार नहीं कर सकती। इस महायज्ञ में सरकार के साथ समाज को भी खड़ा होना पड़ेगा। यह धरती को बचाने का अभियान है। पानी, माटी, धरती बचेगी तो भविष्य बचेगा। यह योजना विशेष रूप से उन क्षेत्रों में लागू की जा रही है जो सूखे और वर्षा पर निर्भर हैं और इन इलाकों में बसे हमारे किसान भाई-बहनों के जीवन में समृद्धि लाने का एक महाभियान है, जहाँ कभी पानी की एक-एक बूँद के लिए संघर्ष करना पड़ता था।

कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आखिर यह वाटरशेड योजना है क्या? मैं उन्हें सरल भाषा में बताता हूँ कि यह केवल एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि लोगों की अपनी, लोगों के लिए चलाई जाने वाली एक क्रांति है। इस योजना का मूलमंत्र है- 卐खेत का पानी खेत में और गाँव का पानी गाँव में卐। इसके तहत हम सब मिलकर खेतों की मेड़ें मजबूत करते हैं, खेत में ही छोटे तालाब बनाते हैं, और छोटे-छोटे नालों पर चेक डैम जैसी जल-संरचनाएं खड़ी करते हैं। इससे बारिश का पानी बहकर बेकार नहीं जाता, बल्कि धीरे-धीरे धरती की प्यास बुझाता है, जिससे भूजल का स्तर बढ़ता है और मिट्टी में लंबे समय तक नमी बनी रहती है।

स योजना की सबसे बड़ी शक्ति इसकी जन-भागीदारी है। गाँव के लोग खुद बैठकर यह तय करते हैं कि तालाब कहाँ खोदना है, मेड़ कहाँ बनानी है और पेड़ कहाँ लगाने हैं। भूमिहीन परिवारों और महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को भी मुर्गीपालन और मधुमक्खी पालन जैसे कामों से जोड़कर उनकी आमदनी बढ़ाने का काम किया जा रहा है। इस योजना के बहुत सुखद परिणाम मिल रहे हैं। इसका सबसे बड़ा लाभ हमारे किसान भाई-बहनों को मिला है, जिनकी आमदनी में 8ब्र से लेकर 70ब्र तक की ठोस वृद्धि हुई है। यह इसलिए संभव हुआ है क्योंकि 2015 से अब तक, सरकार ने ?20,000 करोड़ से अधिक की धनराशि खर्च करके देशभर में 6,382 से अधिक परियोजनाएं चलाई हैं और लगभग 3 करोड़ हेक्टेयर भूमि को फिर से उपजाऊ बनाने का काम किया है।

मध्य प्रदेश के झाबुआ में, जहाँ कभी सूखा एक बड़ी समस्या थी, आज आदिवासी गाँवों में पानी भरपूर है और मिट्टी की उर्वरक शक्ति भी बढ़ गई है। परियोजना क्षेत्र के 22 गाँवों में भूजल स्तर एक मीटर तक बढ़ गया है। इससे खेती में भी परिवर्तन आया है। यहीं के किसान भाई बताते हैं कि गाँव में चेकडैम बनने से अब वे मक्के के साथ-साथ चने की फसल भी ले रहे हैं, जिससे उनकी आमदनी ?50,000 से ?60,000 तक बढ़ गई है। साथ ही झाबुआ की ही परवलिया पंचायत में 12 खेतों में बने खेत तालाबों से किसानों की आमदनी ?1 लाख से ? 1.5 लाख प्रति हेक्टेयर तक बढ़ी है।

इस योजना के तहत 9 लाख से ज्यादा चेक डैम, रिसाव तालाब, खेत तालाब, जैसी वाटरशेड संरचनाएँ बनी हैं। 5.6 करोड़ से ज्यादा श्रम दिवस उपलब्ध हुए हैं, जिससे ग्रामीण रोज़गार में वृद्धि हुई है। वाटरशेड विकास परियोजनाओं के लागू होने से गाँवों में उल्लेखनीय बदलाव आया है। जहाँ पहले पानी की कमी थी, उन परियोजना क्षेत्र में अब 1.5 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा नए इलाक़े में जल स्रोत फैले हैं, यानी 16ब्र का इज़ाफा हुआ है। साथ ही अब किसान पारंपरिक फसलों के अलावा फलों और अन्य पेड़-पौधों की खेती भी करने लगे हैं, जिससे बागवानी और पेड़-पौधों की खेती का दायरा 12ब्र बढ़कर 1.9 लाख हेक्टेयर पहुंच गया है।

राजस्थान के बाड़मेर जैसे रेगिस्तानी इलाके में, जहाँ पानी की कमी किसानों को पलायन पर मजबूर कर रही थी, आज अनार की खेती से हरियाली लौट आई है। योजना के अंतर्गत 120 से अधिक किसानों को अनार के पौधे उपलब्ध कराए गए, जो वहाँ की बालू मिट्टी और सीमित पानी जैसी कठिन परिस्थितियों में भी आसानी से पनप जाते हैं। अनार की खेती ने न केवल आमदनी बढ़ाई, बल्कि बूड़ीवाड़ा गांव के मांगीलाल परांगी का कहना है कि उनके जैसे किसान अब अरंडी छोड़कर बागवानी की ओर बढ़ गए हैं। त्रिपुरा के दाशी रियांग और बिमन रियांग जैसे किसान योजना की मदद से अनानास की बागवानी करके अपनी बंजर भूमि को फिर से उपजाऊ बना रहे हैं और अच्छी आय अर्जित कर रहे हैं।

इस पूरी क्रांति को जन-जन तक पहुँचाने और इसे एक जन-आंदोलन बनाने के लिए हमने 'वॉटरशेड यात्रा' भी निकाली। इस यात्रा के माध्यम से हमने देशभर में जल संरक्षण और भूमि संवर्धन के लिए एक जनजागरण अभियान चलाया। हमने इस योजना में तकनीक का भी भरपूर उपयोग किया है। 'भुवन जियोपोर्टल (सृष्टि)' और 'दृष्टि' मोबाइल ऐप जैसे डिजिटल उपकरणों से योजनाओं की प्रगति की सटीक निगरानी हो रही है। किसानों की मेहनत और हमारी योजनाओं की वजह से, देशभर के फसल क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई है। सैटेलाइट से मिले आँकड़े बताते हैं कि फसल क्षेत्र में लगभग 10 लाख हेक्टेयर (5ब्र की वृद्धि) और जल स्त्रोतों के क्षेत्र में 1.5 लाख हेक्टेयर (16ब्र की वृद्धि) का इजाफा हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि 8.4 लाख हेक्टेयर से ज्यादा बंजर जमीन अब फिर से खेती के योग्य बन चुकी है।

प्रधानमंत्री मोदी जी के कुशल नेतृत्व में आज अमृतकाल में हम सब मिलकर भूमि संरक्षण की एक नई गाथा लिख रहे हैं। यह सिर्फ आँकड़े नहीं हैं, यह हमारे किसानों की मेहनत और उनके बेहतर भविष्य की जीती-जागती कहानी है। जब हम पानी और मिट्टी को बचाएंगे, तभी हम अपनी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित कर पाएंगे। इस संकल्प को मिलकर पूरा करें और किसानों को समृद्ध तथा भारत को विकसित बनाएं।

प्रधानमंत्री मोदी जी का मानना है कि केवल सरकार नहीं, समाज की भागीदारी से ही यह अभियान सफल होगा। उसी सोच के तहत 'वॉटरशेड यात्रा' जैसी पहल से इस योजना को जन-जन तक पहुँचाया गया है और यह एक जनांदोलन बन चुका है। यह भारतीय किसानों की मेहनत और बदलते भविष्य की कहानी है। जब जल और मिट्टी सुरक्षित होंगी, तभी भारत सुरक्षित रहेगा। 2047 तक विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा, जब गाँवों की धरती समृद्ध होगी और किसान खुशहाल होंगे। आइए, मिलकर जल और माटी के इस रक्षा संकल्प को आगे बढ़ाएं।

(लेखक केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री है)

बैंकर्स क्लब, चंडीगढ़ द्वारा साइबर सुरक्षा जागरूकता पर वॉकथॉन

एस. के. सक्सैना

चंडीगढ़, बैंकर्स क्लब, चंडीगढ़ 31 अगस्त, 2025 को प्रातः 6ः15 बजे सुखना झील पर साइबर सुरक्षा जागरूकता वॉकथॉन का आयोजन कर रहा है। इस पहल का उद्देश्य नागरिकों को साइबर सुरक्षा, डिजिटल अनुशासन और सुरक्षित ऑनलाइन व्यवहार के महत्व के प्रति जागरूक करना है।

कार्यक्रम में भारतीय रिज़र्व बैंक के उप-गवर्नर, श्री एम. राजेश्वर राव और कार्यकारी निदेशक, साथ ही पंजाब नेशनल बैंक के महाप्रबंधक एवं बैंकर्स क्लब के सचिव श्री ललित तनेजा, व अन्य उच्च अधिकारियों के साथ इस क्षेत्र से जुड़े वरिष्ठ बैंकर्स भी उपस्थित होंगे।

इस अवसर पर बैंकर्स क्लब के अध्यक्ष एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक श्री विवेक श्रीवास्तव ने कहा, 卐आज के डिजिटल युग में साइबर सुरक्षा जागरूकता स्वास्थ्य जितनी ही आवश्यक है। इस वॉकथॉन के माध्यम से हम प्रत्येक नागरिक को सुरक्षित और जिम्मेदार ऑनलाइन आदतें अपनाने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं।

बैंकर्स क्लब इस पहल को सफल बनाने तथा सुरक्षित डिजिटल भविष्य के लिए सामूहिक प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद रजि. की ओर से परविंदर शर्मा को पंजाब प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत किया

ब्राह्मण समाज में खुशी की लहर — सुभाष शर्मा

चंड़ीगढ़, अगस्त 29 [आमने सामने ब्यूरो चीफ]- भठिंडा पंजाब के मूल निवासी परविंदर शर्मा की ओर से समाज के प्रति उत्कृष्ट सेवाओं के चलते वह किसी जान पहचान के मोहताज नहीं हैं।ब्राह्मण समाज के उत्थान / सशक्तिकरण एवं समाज कल्याणार्थ कार्यों में विशेष योगदान प्रदान कर रहे हैं। वह समाजिक,धार्मिक कार्यों के साथ साथ जरूरतमंद परिवारों की यथायोग्य समर्थानुसार सहयोग प्रदाय करने हेतु सदैव अग्रणी रहते हैं। शर्मा अति संस्कारिक,कर्मठ एवं निष्ठावान इंसान हैं जो जनकल्याणार्थ सेवाओं को प्रसन्नचित से संपन्न कर रहे है। इनकी अति उत्कृष्ट सेवाओं को मध्य नजर रखते हुए अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद पंजीकृत के राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्राह्मण प्रवीण कुमार मिश्रा की ओर से परविंदर शर्मा को 卐पंजाब प्रदेश का अध्यक्ष卐 मनोनीत किया। नवनियुक्त पंजाब प्रदेश अध्यक्ष ने अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद रजि॰ के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं कार्यकारिणी कमेटी के सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यगणों का हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए आश्वासन दिया कि वह उक्त जिम्मेदारी को परिश्रम एवं लगन से निभाएंगे। जिसके चलते समाज के अंदर समारसता की भावना व्यक्त हो सके ,क्यों कि भगवान श्री परशुराम जी ने अपने सिद्धांतों में स्पष्ट कर दिया था। ब्राह्मण समाज के विशेष प्रतिनिधि पंडित सुभाष चंद्र शर्मा ने उक्त संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष का इस नियुक्ति हेतु हार्दिक आभार व्यक्त किया। नवनियुक्त पंजाब प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति से ब्राह्मण समाज में खुशी की लहर है।

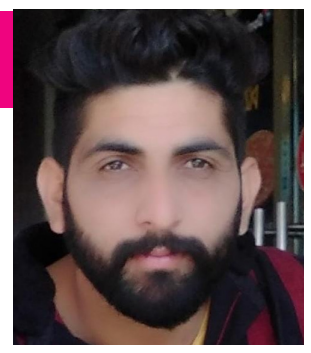

अरमान हस्पताल की गलती पर जाँच के बाद अवश्य सख्त कानूनी कारवाई होगी-अशोक सरीन हिक्की

पंकज

पंजाब मानवाधिकार कमीशन द्वारा पुलिस कमिश्नर और जालंधर सिविल सर्जन जालंधर को तीस साल की टीचर सोनम मुल्तानी की माइनर स्पाइन सर्जरी के बाद पेट की कोई नस कट जाने के मामले मे स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश पर

नेशनल मैडिकल कमीशन मे भी शिकायत करेंगे

इस मामले को उठाने वाले जालंधर भाजपा के महामंत्री अशोक सरीन ने कहा इस बेहद दुखद घटना के चलते मेहनती पढ़ी लिखी सरकारी टीचर के ऑपरेशन के दौरान हुई गलती के मामले मे अंतिम पढ़ाव मे चल रही डॉक्टरों समेत फॉरेंसिक एक सपट' वन्यूरोलॉजिस्ट की जाँच के बाद अवश्य सख्त कानूनी कारवाई होगी ताकि भविष्य मे किसी भी परिवार को सदस्य ना मरे ।इस बारे में सरीन ने बताया की जल्द अरमान हॉस्पिटल का लाइसेंस कैंसल कर डॉ की प्रैक्टिस पर रोक लगाने की शिकायत सख्त कानूनी कारवाई करवाने की दर्ज करवाई जायेगी।

कैबिनेट मंत्री मोहिंदर भगत ने सिविल अस्पताल का किया दौरा , डायरिया से पीड़ित मरीजों का हाल-चाल जाना

स्वास्थ्य विभाग को उचित स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश, नगर निगम को स्वच्छ पीने का पानी उपलब्ध करवाने के निर्देश

रमन कुमार

जालंधर, पंजाब के बागवानी, स्वतंत्रता सेनानी एवं रक्षा सेवाएं कल्याण मंत्री मोहिंदर भगत ने आज सिविल अस्पताल जालंधर का दौरा किया और डायरिया से पीड़ित मरीजों का हालचाल जाना। इस अवसर पर उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को मरीजों का उचित सुनिश्चित करने और किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए। मरीजों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली राज्य सरकार सरकारी अस्पतालों में उचित स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि किसी भी मरीज को घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि मरीजों का बहुत अच्छा इलाज किया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री ने नगर निगम के अधिकारियों को शहरवासियों के लिए स्वच्छ पीने का पानी सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शहर में पानी की सप्लाई पाइपों का गहन निरीक्षण किया जाए और यदि कोई कमी पाई जाती है, तो उसे तुरंत ठीक किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि डायरिया से पीड़ित मरीज के क्षेत्र में तुरंत टैंकरों के माध्यम से पेयजल उपलब्ध करवाया जाए। इस अवसर पर सिविल सर्जन डा. गुरमीत लाल के अलावा अन्य डॉक्टर भी मौजूद थे।

पंजाब सरकार के प्रयासों से 5290 लोगों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से बाहर निकाला गया

मुख्यमंत्री के निर्देशों पर हर मंत्री और विधायक बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में ग्राउंड ज़ीरो पर डटे

सुभाष चंद्र

चंडीगढ़, -हिमाचल में हुई भारी बारिश और बादल फटने तथा पंजाब में हुई तेज़ बरसात के कारण आई बाढ़ से निपटने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई वाली पंजाब सरकार की ओर से युद्ध स्तर पर राहत कार्य चलाए जा रहे हैं। पंजाब के कैबिनेट मंत्रियों और स्थानीय विधायकों ने स्वयं ग्राउंड ज़ीरो पर जाकर राहत कार्यों का जायज़ा लिया। पंजाब सरकार के प्रयासों से 5290 लोगों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से बाहर निकाला गया, जिनमें गुरदासपुर में 2000, अमृतसर में 710, फिरोज़पुर में 2000, कपूरथला में 480 और फाज़िल्का में 100 लोगों को रेस्क्यू किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए पंजाब सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री के दिशा-निर्देशों के अनुसार आज राज्य के कैबिनेट मंत्रियों ने विभिन्न ज़िलों में जाकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे राहत कार्यों का निरीक्षण किया गया। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने आज ज़िला प्रशासकीय कॉम्प्लेक्स संगरूर में बाढ़ राहत कार्यों का जायज़ा लिया। उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा गाँव सतोझ हरआओ, डस्का और संगतपुरा में बाढ़ पीड़ित लोगों की मदद के लिए टीमों को लगाया गया है। उन्होंने कहा कि बाढ़ से हुए नुकसान संबंधी विशेष गिरदावरी करवा कर पीड़ितों को मुआवज़ा दिया जाएगा।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज जम्मू का दौरा किया और जम्मू संभाग के वर्षा, बाढ़ एवं भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान का जायजा लिया

मनदीप कौर

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज जम्मू का दौरा किया और जम्मू संभाग के वर्षा, बाढ़ एवं भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान का जायजा लिया। गृह मंत्री जम्मू में चक मांगू गांव के बाढ़–प्रभावित लोगों से भी मिले। श्री अमित शाह ने तवी पुल, शिव मंदिर और जम्मू में बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए घरों का भी निरीक्षण किया। दौरे के बाद केन्द्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय बैठक में ताज़ा स्थिति की समीक्षा की गई। बैठक में जम्मू–कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा, मुख्यमंत्री श्री उमर अब्दुल्ला, केन्द्र सरकार एवं केन्द्रशासित प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। केन्द्रीय गृह मंत्री ने हाल की घटनाओं में हुई जन–हानि पर दुख व्यक्त किया। श्री शाह ने कहा कि संकट की इस घड़ी में, पहले दिन से ही प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने केन्द्रशासित प्रदेश के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री से बात की है और भारत सरकार ने बचाव कार्यों में अपनी पूरी शक्ति लगा दी है। श्री शाह ने कहा कि केन्द्रशासित प्रदेश और सभी एजेंसियों ने मिलकर संभावित नुकसान को बहुत कम किया है और समन्वित प्रयासों के साथ हम कई जानें बचाने में सफल हुए हैं। श्री अमित शाह ने कहा कि हमारी सभी अर्ली वॉर्निंग एप्स की पद्धतियों, उनकी सटीकता और उनकी जमीनी पहुँच का क्रिटिकल एनिलिसिस होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बार–बार समीक्षा कर व्यवस्था में सुधार करना ही हमें ज़ीरो कैज़ुअल्टी अप्रोच की दिशा में लेकर जा सकता है। केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि मौसम विभाग व ह्ष्ठक्रू को डेटा एनालिटिक्स और ्रढ्ढ के उपयोग से बादल फटने के कारणों का अध्ययन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारतीय खाद्य निगम (स्नष्टढ्ढ) पर्याप्त राशन की व्यवस्था करे और 10 दिन बाद कनेक्टिविटी की स्थिति को देखते हुए राशन की डिलिवरी ऑफलाइन करने का निर्णय लिया जा सकता है। श्री अमित शाह ने कहा कि एक–दो दिन में ही गृह मंत्रालय की सर्वेक्षण टीमें यहाँ नुकसान का जायजा लेने आएंगी और उसके बाद सहायता भी प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य और जल विभाग को सक्रिय होकर जल आपूर्ति और स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि सेना, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल और वायु सेना के मेडिकल दस्तों की सहायता ली जा सकती है। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि चूँकि जम्मू–कश्मीर प्राकृतिक आपदा–संभावित क्षेत्र है इसीलिए केन्द्र के हिस्से के रूप में राज्य आपदा मोचन निधि के लिए 209 करोड़ रुपये की राशि केन्द्रशासित प्रदेश को आवंटित की गई है, जिससे यहाँ राहत कार्य शुरू हो गया है। गृह मंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार और केन्द्रशासित प्रदेश आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा समय पर दी गई चेतावनियों से जन–माल के नुकसान को कम करने में मदद मिली। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल सेना, केन्द्रशासित प्रदेश आपदा मोचन बल , अन्य प्रतिक्रिया दल, सभी अलर्ट पर थे और हेलीकॉप्टर भी तैयार थे। उन्होंने कहा कि सेना और ह्ष्ठक्रस्न की तैनाती के बारे में भी सभी को सूचित कर दिया गया था। श्री अमित शाह ने कहा कि लोगों की निजी संपत्ति को नुकसान पहुँचा है और क्षतिग्रस्त घरों के लिए स्ष्ठक्रस्न के तहत सहायता का आकलन किया जा रहा है और इसे जल्द से जल्द वितरित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कई सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं और उनकी मरम्मत का काम शुरू हो गया है। अधिकांश सड़कों पर यातायात शुरू हो गया है और जहाँ भी ज़रूरत है, राहत सामग्री पहुँचनी शुरू हो गई है। प्रभावित क्षेत्रों में 80 प्रतिशत से अधिक बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई है, लोगों को शुद्ध पेयजल मिलने लगा है और स्वास्थ्य सुविधाएँ सुचारू रूप से चल रही हैं। महत्वपूर्ण क्षेत्रों का बुनियादी ढांचा प्रभावित हुआ है और उसकी अस्थायी बहाली का काम युद्धस्तर पर चल रहा है।

जम्मू–कश्मीर प्रशासन द्वारा नुकसान का आकलन किया जा रहा है और हरसंभव सहायता प्रदान की जाएगी। केन्द्रीय गृह मंत्री ने सभी एजेंसियों के प्रयासों की सराहना की और कहा कि केन्द्रशासित प्रदेश ने अत्यंत शीघ्रता और कुशलता से सफल बचाव अभियान चलाया। एहतियात के तौर पर 5000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया है। ह्ष्ठक्रस्न की 17 टीमें और सेना की 23 टुकड़ियाँ, भारतीय वायु सेना के हेलीकॉप्टर, ञ्जष्ठक्रस्न, जम्मू–कश्मीर पुलिस और केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (ष्टक्रस्नह्य) के जवान अभी भी पूरे अभियान में लगे हुए हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं। केन्द्रशासित प्रदेश प्रशासन द्वारा राहत शिविरों में स्वास्थ्य सुविधाओं और भोजन की व्यवस्था की गई है और स्थिति बहुत जल्द सामान्य हो जाएगी। केन्द्रीय गृह मंत्री ने जम्मू–कश्मीर के लोगों को आश्वासन दिया कि संकट की इस घड़ी में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में, केन्द्र सरकार जम्मू और कश्मीर के लोगों के साथ मजबूती के साथ खड़ी है और जनता की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करते हुए, पुनर्वास और पुनर्निर्माण को सुगम बनाने के लिए त्वरित राहत, वित्तीय सहायता और तकनीकी सहायता प्रदान कर रही है।

पंजाब सरकार ने बाढ़ प्रभावित इलाकों से 6,600 लोगों को बचाया

सुरक्षा और सहायता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावित जिलों में 88 राहत कैम्प स्थापित

रविंद्र कुमार

जालंधर, पंजाब सरकार ने बाढ़ प्रभावित इलाकों से 6,600 लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर स्थापित राहत शिविरों में पहुंचाया है। डिप्टी कमिश्नर डा. हिमांशु अग्रवाल और पंजाब पर्यटन एवं सांस्कृतिक मामलों के विभाग के सलाहकार दीपक बाली ने जालंधर में स्टेट बाढ़ कंट्रोल रूम का निरीक्षण करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने पूरे बचाव और राहत कार्यों की निगरानी के लिए जालंधर में एक राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम(0181–2240064) स्थापित किया है। इस पहल का उद्देश्य प्रभावित लोगों तक समय पर राहत सामग्री पहुंचाना सुनिश्चित करना है। विस्तृत जानकारी देते हुए डिप्टी कमिश्नर एवं सलाहकार श्री बाली ने बताया कि बाढ़ से कुल 835 गांव प्रभावित हुए हैं, जिनमें अमृतसर में 14, बठिंडा में 21, बरनाला में 7, लुधियाना में 20, पठानकोट में 81, फाजिल्का में 20, मानसा में 11, तरनतारन में 45, एस.बी.एस. नगर में 3, मलेरकोटला में 1, श्री मुक्तसर साहिब में 64, संगरूर में 22, फिरोजपुर में 93, एस.ए.एस. नगर में 1, कपूरथला में 107, गुरदासपुर में 202, फतेहगढ़ साहिब में 1, मोगा में 35, रूपनगर में 2 और होशियारपुर में 85 गांव शामिल है। उन्होंने बताया कि 6,600 से ज़्यादा लोगों को बचाया गया है, जिनमें फ़िरोज़पुर में 2007, गुरदासपुर में 2200, पठानकोट में 1100, कपूरथला में 220, होशियारपुर में 1052 और मोगा में 20 लोग शामिल है। इन लोगों को बाढ़ प्रभावित ज़िलों में सरकार द्वारा स्थापित 88 राहत शिविरों में भेजा गया है।

उन्होंने आश्वासन दिया कि इन शिविरों में भोजन, दवाइयां और अन्य राहत सामग्री पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। उन्होंने प्रभावित परिवारों को अधिक से अधिक सहायता प्रदान करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई और कहा कि इस संकट में लोगों की कठिनाइयों को कम करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फंसे लोगों से अपील की कि वे सरकार से मदद के लिए राज्य बाढ़ कंट्रोल रूम के नंबर 0181–2240064 पर संपर्क करें ताकि राहत सामग्री या बचाव कार्यों से संबंधित अधिकारियों द्वारा तुरंत कार्रवाई की जा सके।

अमन अरोड़ा द्वारा केंद्रीय मंत्री से हुनरमंद विकास पहलों के लिए एकल संपर्क बिंदु मनोनीत करने की अपील

अरोड़ा ने कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय योजनाओं में 3 से 5 वर्षों की निरंतरता लाने का सुझाव दिया

सुभाष चंद्र

चंडीगढ़, पंजाब के रोजगार उत्पत्ति, कौशल विकास और प्रशिक्षण मंत्री और आम आदमी पार्टी के राज्य अध्यक्ष श्री अमन अरोड़ा ने आज केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री श्री जयंत चौधरी से कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के सभी कौशल विकास पहलों के लिए एकल संपर्क बिंदु के रूप में मनोनीत करने की अपील की, ताकि केंद्रीय सरकार की कौशल विकास योजनाओं की निगरानी और क्रियान्वयन में एकरूपता लाई जा सके। आज यहां एक होटल में आयोजित कौशल विकास मंत्रियों के क्षेत्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री अमन अरोड़ा ने कौशल विकास में वृद्धि से संबंधित दो प्रमुख उपायों का सुझाव दिया कि कौशल योजनाओं में 3–5 वर्षों की निरंतरता सुनिश्चित की जाए, ताकि युवाओं को बेहतर योजनाबंदी और विकल्प प्रदान किए जा सकें और प्रदेशीय कौशल मिशनों के माध्यम से केंद्रीय कौशल प्रशिक्षण योजनाओं को लागू किया जा सके, जिससे अधिक प्रभावी परिणाम प्राप्त करने के लिए क्रियान्वयन और निगरानी में उनकी विशेषज्ञता का लाभ उठाया जा सके। कौशल विकास में राज्य की महत्वपूर्ण प्रगतियों को उजागर करते हुए, श्री अमन अरोड़ा ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता वाली पंजाब सरकार ने 2024 में 'पंजाब कौशल विकास योजना' की शुरुआत की थी, जिसमें 10,654 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया। इसके अलावा, राज्य सरकार द्वारा विभिन्न कौशलों में मुफ्त प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए आइबीएम, माइक्रोसाफ्ट और नैस्कॉम जैसी प्रमुख कंपनियों से भागीदारी की गई है। राज्य सरकार का उद्देश्य आइटीआइज़ को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाना, उद्यमिता को प्रोत्साहित करना और कौशल प्रशिक्षण के लिए डिजिटल एकीकरण का लाभ उठाना है, ताकि पंजाब के युवाओं को कुशल बनाया जा सके और उनकी रोजगारयोग्यता में वृद्धि की जा सके।

जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने चिक-चिक हाउस के पास गन पॉइंट पर कार लूटने वाले अपराधियों को मुठभेड़ के बाद कुछ ही घंटों में किया गिरफ्तार

एस. के. सक्सैना

जलंधर, शहर में आपराधिक गतिविधियों के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल करते हुए जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने चिक–चिक हाउस के पास कार लूटने के मामले में शामिल अपराधियों को मुठभेड़ के बाद कुछ ही घंटों में दो गाड़ियों और हथियारों सहित गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस कमिश्नर श्रीमती धनप्रीत कौर ने जानकारी देते हुए बताया कि 28.08.2025 को चिक–चिक हाउस के पास परमजीत सिंह से गन पॉइंट पर गाड़ी लूटने के संबंध में थाना डिवीजन नंबर 2 में मुकदमा नंबर 109, दिनांक 28.08.2025, धारा 304(2), 3(5) ब्ह्रह्र 2023 के तहत दर्ज किया गया। इस घटना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए कमिश्नरेट जलंधर ने एक टीम का गठन किया, जिसकी निगरानी डीसीपी (इन्वेस्टिगेशन) मनप्रीत सिंह ढिल्लों, एडीसीपी (इन्वेस्टिगेशन) जयंत पुरी, एडीसीपी परमजीत सिंह और एसीपी (सेंट्रल) अमनदीप सिंह ने की। इस टीम का नेतृत्व थाना डिवीजन नंबर 2 के मुख्य अधिकारी जसविंदर सिंह और सीआईए इंचार्ज सुरिंदर कुमार ने किया। जांच के दौरान सीसीटीवी कैमरों, तकनीकी सहायता और अन्य स्रोतों की मदद से अपराधियों की तलाश की गई। पुलिस पार्टी रईया से करीब आधा किलोमीटर अमृतसर की ओर पहुंची, जहां लूटी गई गाड़ी (क्क10–छ्ठ–9944) और एक अन्य गाड़ी (क्क02–ब्ल–9103)द्ध देखी गई। अपराधियों ने पुलिस को देखकर भागने की कोशिश की और गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने मनजोत सिंह उर्फ मनी, निवासी बुद्धा थेह, थाना ब्यास, जिला अमृतसर देहाती को काबू कर लिया और उसके पास से 7.62 एमएम पिस्तौल बरामद की गई। इसके खिलाफ थाना ब्यास, जिला अमृतसर देहाती में मुकदमा नंबर 167, दिनांक 28.08.2025, धारा 109, 221, 136 ब्ह्रह्र और 25 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि इस कार्रवाई के दौरान दूसरे आरोपी हजूर सिंह उर्फ मानव, निवासी बुद्धा थेह, थाना ब्यास, जिला अमृतसर देहाती को रईया की ग्रीन एवेन्यू कॉलोनी से लूटी गई गाड़ी (PB10–DN–9944) सहित गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि आरोपियों का पुलिस रिमांड प्राप्त किया गया है ताकि उनसे अन्य वारदातों के बारे में गहन पूछताछ की जा सके। हजूर सिंह के खिलाफ पहले से ही आपराधिक धाराओं के तहत 3 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि किसी भी तरह की गैरकानूनी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और शहर में कानून–व्यवस्था खराब करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

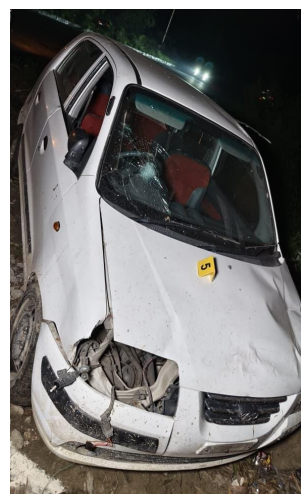

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की छमाही बैठक पंचकूला में संपन्न

बैठक में नगर के विभिन्न सदस्य कार्यालयों के 84 अध्यक्षों व प्रतिनिधियों ने भाग लिया

पंकज

पंचकूला , अगस्त॰ नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, पंचकूला – जो नगर के केंद्रीय सरकारी कार्यालयों, उपक्रमों तथा बैंकों की संयुक्त समिति है और राजभाषा कार्यान्वयन के लिए कार्यरत है – की वर्ष 2025–26 की प्रथम छमाही बैठक का आयोजन पंचकूला में किया गया। बैठक की अध्यक्षता सुश्री कोमल जगपाल, प्रधान आयकर आयुक्त, पंचकूला ने की तथा राजभाषा विभाग की ओर से संयुक्त निदेशक श्री कुमार पाल शर्मा ने प्रतिनिधित्व किया। बैठक में नगर के विभिन्न सदस्य कार्यालयों के 84 अध्यक्षों व प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस अवसर पर वर्ष 2025–26 के दौरान नगर स्तर पर आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2024–25 में आयोजित प्रतियोगिताओं के 57 विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए। इस अवसर पर श्री कुमार पाल शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि कंठ, कलम और कंप्यूटर के माध्यम से राजभाषा की प्रगति सुनिश्चित की जा सकती है। अध्यक्षीय संबोधन में सुश्री कोमल जगपाल ने सभी कार्यालय अध्यक्षों को अपने–अपने कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन के सुचारू और सार्थक प्रयास करने पर बल दिया। उन्होंने आसान हिंदी तथा मिश्रित भाषा के प्रयोग द्वारा राजभाषा लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रेरित किया। अंत में समिति सचिव ने सभी सदस्यों की गरिमामयी उपस्थिति हेतु धन्यवाद ज्ञापित किया।

आकाशवाणी जालंधर ने सफलतापूर्वक प्रसारित किया 15वां हॉकी इंडिया पुरुष जूनियर राष्ट्रीय चैम्पियनशिप 2025 का फाइनल मैच

एसके सक्सैना

जालंधर, आकाशवाणी जालंधर ने 15वीं हॉकी इंडिया पुरुष जूनियर राष्ट्रीय चैम्पियनशिप 2025 के फाइनल मैच का सफल प्रसारण एफ एम रेनबो 102.7 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप पर किया। प्रतियोगिता की कॉमेंट्री का संचालन कुलविंदर सिंह कांग ने किया, जबकि राजिंदर सिंह ने समय–समय पर एफएम अपडेट प्रस्तुत किए। बीरिंदर सिंह ने प्री और पोस्ट शो का संचालन किया। कार्यक्रम निर्माण की ज़िम्मेदारी प्रतीष्ठा जैन, खेल कार्यक्रम प्रभारी, आकाशवाणी जालंधर ने निभाई। तकनीकी दल में सचिन सिंह, सूरज और राहुल शर्मा शामिल रहे। स्टूडियो में आर जे निशा बत्रा और सौरव कुमार राजू (ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट) ने सहयोग प्रदान किया। सम्पूर्ण प्रसारण गुरविंदर सिंह, कार्यक्रम कार्यकारी तथा परमजीत सिंह, कार्यक्रम प्रमुख, आकाशवाणी जालंधर के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। आकाशवाणी जालंधर श्रोताओं तक राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताएँ पहुँचाने और खेल प्रसारण को प्रोत्साहन देने के अपने संकल्प पर लगातार अग्रसर है।

जालंधर भाजपा शहरी कल चारों विधानसभा हल्कों में मान सरकार का पुतला फूंक प्रदर्शन करेगी-सुशील शर्मा

जालंधर (गुरप्रीत) भारतीय जनता पार्टी जिला शहरी अध्यक्ष सुशील शर्मा की अध्यक्षता में कल भाजपा शहरी मान सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ चारों विधानसभा हल्कों में पुतला फूंक प्रदर्शन करेगी। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार की धक्केशाही के ख़िलाफ़ अब पार्टी चुप नहीं बैठेगी और सड़कों पर उतर कर रोष स्वरुप भाजपा प्रदेश की मान सरकार का दोगला चेहरा जनता के सामने बेनकाब करेगी।

इंडियन एयर फोर्स की ओपन भर्ती रैली शुरू, पहले दिन 6000 उम्मीदवारों ने लिया हिस्सा

बारिश भी युवाओं के उत्साह को कम नहीं कर पाई

रमन कुमार

जालंधर, जिला प्रशासन के सहयोग से भारतीय वायु सेना ने आज स्थानीय सरकारी आर्ट्स एवं स्पोर्ट्स कॉलेज में खुली भर्ती रैली शुरू की, जिसमें बारिश के बावजूद पहले दिन लगभग 6000 अभ्यर्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

एस डी.एम. आदमपुर विवेक कुमार मोदी (अतिरिक्त प्रभार, अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर ग्रामीण विकास) ने बताया कि भारतीय वायु सेना की खुली भर्ती रैली बारिश के बीच सुबह 4॰30 बजे शुरू हुई, जिसमें हिमाचल प्रदेश, जम्मू–कश्मीर और लद्दाख से लगभग 6000 अभ्यर्थियों ने भाग लिया। रैली के दौरान, पहले राउंड में उम्मीदवारों ने 7 मिनट में 1600 मीटर की दौड़ पूरी की। इसके बाद कुछ अन्य शारीरिक परीक्षण किए गए। फिजिकल टेस्ट के बाद, आवेदकों की लिखित परीक्षा भी ली गई। उन्होंने बताया कि इस लिखित परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों को 28 अगस्त को ग्रुप डिस्कशन और अन्य मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के लिए फिर से बुलाया जाएगा। जिला रोजगार उत्पत्ति, कौशल विकास एवं प्रशिक्षण ब्यूरो की उपनिदेशक नीलम महे ने अधिक जानकारी देते हुए बताया कि पंजाब राज्य और चंडीगढ़ के लड़कों के लिए भर्ती रैली 30 अगस्त को और लड़कियों के लिए भर्ती रैली 2 सितंबर को होगी। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे इस भर्ती रैली में बड़ी संख्या में भाग लें और सरकारी क्षेत्र में रोजगार के इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाएं। गौरतलब है कि भर्ती रैली के दौरान जम्मू–कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में युवा पहुंचे थे। रैली के दौरान युवाओं का जोश काबिले तारीफ था, जिनका उत्साह बारिश भी कम नहीं कर पाई।

ट्राई द्वारा साइबर हाइजीन पर आउटरीच प्रोग्राम का आयोजन

डीएनडी 3.0 ऐप और संचार साथी पोर्टल के बारे में किया गया जागरूक, पीड़ित मोबाइल फोन पर चोरी और साइबर धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज करा सकेंगे

रमन कुमार

पटियाला–डिजिटल सुरक्षा और उपभोक्ता सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई), रीजनल ऑफिस दिल्ली द्वारा सरकारी मोहिंद्रा कॉलेज, पटियाला में साइबर हाइजीन पर उपभोक्ता आउटरीच प्रोग्राम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम पटियाला कंज़्यूमर एंड टेलीफोन सब्सक्राइबर्स फोरम के सहयोग से करवाया गया, जिसमें स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम में छात्रों, फैकल्टी सदस्यों, टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं और ट्राई से पंजीकृत उपभोक्ता समूहों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को साइबर खतरों, स्पैम संचार और आधुनिक डिजिटल युग में सुरक्षित ऑनलाइन प्रक्रियाओं को अपनाने के महत्व के बारे में जागरूक करना था। कार्यक्रम के दौरान पटियाला पुलिस की साइबर क्राइम सेल के अधिकारियों ने मंच से संबोधन किया। उन्होंने लोगों को बढ़ते साइबर अपराधों, फ़िशिंग हमलों, वित्तीय धोखाधड़ी और साइबर अपराधियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सोशल इंजीनियरिंग तकनीकों के बारे में जानकारी दी। अपने संबोधन में उन्होंने व्यक्तिगत जागरूकता और ज़िम्मेदार डिजिटल व्यवहार की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया। इसके अलावा, ट्राई के वरिष्ठ अधिकारी राजेश त्रिपाठी और सुशील कुमार बंसल ने उपभोक्ताओं को अवांछित संचार और ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाने के लिए उठाए जा रहे नियामक उपायों और उपभोक्ता–अनुकूल पहलों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने ट्राई द्वारा स्पैम रोकने, पारदर्शिता सुनिश्चित करने और दूरसंचार क्षेत्र में उपभोक्ता अधिकारों को मज़बूत करने के लिए किए जा रहे प्रयासों पर प्रकाश डाला।

किशोर न्याय अधिनियम-2015 की धारा 74 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए-जिला बाल सुरक्षा अधिकारी

अधिनियम का उल्लंघन करने पर 6 महीने की कैद या 2 लाख रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकते

कैप्टन सुभाष चंद्र

जालंधर, जिला बाल एवं सुरक्षा अधिकारी अजय भारती ने जानकारी सांझा करते हुए बताया कि किशोर न्याय अधिनियम–2015 की धारा 74 का कड़ाई से अनुपालन आवश्यक है क्योंकि यह बच्चों (कानून का उल्लंघन करने वाले, देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले, या पीड़ित/गवाह) की पहचान उजागर होने से बचाता है, जिससे उनकी निजता और गरिमा की रक्षा होती है। उन्होंने कहा कि यौन और शारीरिक शोषण के शिकार या किशोर न्याय बाल देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम–2015 के अंतर्गत आने वाले बच्चों (गुमशुदा बच्चे, घर से भागे हुए, परित्यक्त बच्चे और अनाथ) की जानकारी सोशल मीडिया, समाचार पत्रों या किसी अन्य माध्यम से प्रकाशित नहीं की जा सकती और ऐसा करना किशोर न्याय अधिनियम–2015 की धारा 74 का उल्लंघन है। उन्होंने बताया कि इस अधिनियम का उल्लंघन करने पर 6 माह का कारावास या 2 लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते है। जिला बाल एवं संरक्षण अधिकारी ने इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया के प्रतिनिधियों को निर्देश दिया है कि वे ऐसे बच्चों की पहचान समाचार पत्रों, सोशल मीडिया या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रकाशित करने से बचें जो कानून का उल्लंघन करते हैं या जिन्हें देखभाल या संरक्षण की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि किशोर न्याय अधिनियम की धारा–74 के अनुसार, ऐसे बच्चों की खबर समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, समाचार पत्रों या ऑडियो–वीडियो मीडिया या किसी अन्य तरीके से, पूछताछ या जांच या न्यायिक कार्यवाही से संबंधित किसी भी प्रकार के संचार में प्रकाशित करते समय, किसी भी रिपोर्ट में नाम, पता या स्कूल या किसी अन्य विशेष जानकारी का खुलासा नहीं किया जाएगा और न ही ऐसे किसी बच्चे की तस्वीर प्रकाशित की जाएगी। श्री भारती ने आगे बताया कि किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम–2015 बच्चों (जो 18 वर्ष से कम आयु के है) के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। यह अधिकार बच्चों की सुरक्षा, विकास और भागीदारी सुनिश्चित करते है, चाहे उनकी जाति, धर्म, लिंग या सामाजिक स्थिति कुछ भी हो।

पढ़ें भारत हर ख़बर सच के साथ
आज तक आमने-सामने
पंजाब, जम्मू-कश्मीर, दिल्ली एवं हरियाणा
Email : aajtakaamnesaamne.in@gmail.com
RNI No-Punhin2013/54688

जब पानी छीनना था तो सारे कानून ताक पर रख दिए, अब कोई मदद के लिए आगे नहीं आ रहा-बरिंदर गोयल ने केंद्र और पड़ोसी राज्यों को आड़े हाथों लिया

कहा, देश का पेट भरने वाले पंजाब को राहत पैकेज दे केंद्र सरकार, फाज़िल्का में बाढ़ राहत प्रबंधों का लिया जायज़ा

रविंद्र कुमार

चंडीगढ़/फाज़िल्का, 28 अगस्त–पंजाब के जल संसाधन मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने आज केंद्र सरकार और पड़ोसी राज्यों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कुछ महीने पहले जब पंजाब से पानी छीनना था तो केंद्र सरकार सारे नियम–कानून ताक पर रखकर पंजाब का पानी लूटने पर उतारू था, लेकिन अब जब पंजाब को मदद की ज़रूरत है तो कोई भी आगे नहीं आ रहा। आज यहाँ कावांवाली पत्तन पर बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा करते समय पत्रकारों से बातचीत करते हुये कैबिनेट मंत्री श्री बरिंदर कुमार गोयल ने कहा कि देश के लिए अनाज पैदा करने वाले पंजाब में आई बाढ़ की स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार का फ़र्ज़ बनता है कि वह बिना माँगे पंजाब को राहत पैकेज दें। उन्होंने कहा कि जो लोग पंजाब का पानी

इस्तेमाल करते हैं, उन्हें भी इस मुश्किल घड़ी में पंजाब की मदद के लिए आगे आना चाहिए था। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पहाड़ों और पंजाब में हुई बारिश के कारण इस बार बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है, लेकिन फिर भी पंजाब सरकार लोगों को तुरंत हर संभव मदद पहुँचा रही है और सभी विभागों की टीमें फील्ड में हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान और उनकी कैबिनेट के सभी मंत्री व विधायक लगातार जनता के बीच पहुँच रहे हैं और राहत कार्यों को लोगों तक पहुँचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने तो अपना हेलीकॉप्टर भी राहत कार्यों के लिए लगा दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान पहले ही विशेष गिरदावरी के आदेश दे चुके हैं और हुए नुकसान की भरपाई मुआवज़ा देकर की जाएगी। उन्होंने कहा कि राहत केंद्र स्थापित किए गए हैं और प्रभावित लोगों को पानी वाले इलाकों से निकालकर राहत शिविरों में भेजा जा रहा है, जहाँ लोगों को खाने–पीने और रहने की सारी सुविधा पंजाब सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित गाँवों में हरे चारे और भूसे की कमी को देखते हुए पूरे पंजाब के लोग एक–दूसरे की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। श्री बरिंदर कुमार गोयल ने कहा कि एनडीआरएफ की टीमों के अलावा सेना भी ज़िला प्रशासन की मदद कर रही है और आज भी 100 से अधिक लोगों को किश्तियों के माध्यम से बाहर निकाला गया है। ज़िले में सात राहत शिविर चल रहे हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने यह भी कहा कि फिलहाल बाँधों में पानी की आमद में कमी आई है, जो राहत की खबर है।

आईआईटी रोपड़ ने एक्रोपोलिस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च (एआईटीआर), इंदौर के साथ मिलकर अपनी 15वीं साइबर-फिजिकल सिस्टम्स (सीपीएस) लैब शुरू की

एसके सक्सैना

रोपड़, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), रोपड़ ने भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के राष्ट्रीय अंत:विषय साइबर–फिजिकल सिस्टम्स मिशन (एनएम–आईसीपीएस) के अंतर्गत एक्रोपोलिस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च (एआईटीआर), इंदौर में अपनी 15वीं साइबर–फिजिकल सिस्टम्स (सीपीएस) लैब का उद्घाटन किया है। यह मध्य प्रदेश और मध्य भारत की पहली सीपीएस लैब है, जो उभरती प्रौद्योगिकियों में उन्नत अनुसंधान, नवाचार और कौशल विकास तक पहुँच बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। कार्यक्रम की शुरुआत सीपीएस लैब के अनावरण के साथ हुई, जहाँ आईआईटी रोपड़ की तकनीकी टीम ने अत्याधुनिक सेटअप और उपकरणों का प्रदर्शन किया, और बताया कि कैसे ये सुविधाएँ छात्रों और शोधकर्ताओं को व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने और वास्तविक दुनिया की सीपीएस परियोजनाओं पर काम करने में सक्षम बनाएँगी। इस अवसर पर एआईटीआर के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष अशोक सोजतिया, एआईटीआर के अध्यक्ष इंजी. गौरव सोजतिया और एआईटीआर के मानव संसाधन विभाग के प्रमुख श्री ललित दुबे सहित आईआईटी रोपड़ और एक्रोपोलिस संस्थान के वरिष्ठ गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे। स्वागत संबोधन में एआईटीआर के निदेशक प्रो. (डॉ.) एस. सी. शर्मा ने छात्रों और शिक्षकों को भविष्य के लिए तैयार कौशल से लैस करने में इस तरह के सहयोग के महत्व पर बल दिया। आईआईटी रोपड़ के निदेशक डॉ. राजीव आहूजा ने सीपीएस लैब्स को मध्य भारत में पहली और डीएसटी के एनएम–आईसीपीएस के तहत 15वीं लैब के रूप में रेखांकित किया, जिसका उद्देश्य स्वदेशी टूलकिट के माध्यम से व्यावहारिक शिक्षा और नवाचार को आगे बढ़ाना है। प्रो. निशा राठी ने सीपीएस लैब का परिचय दिया और मुख्य अतिथि, आईआईटी रोपड़ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फाउंडेशन की सीईओ डॉ. राधिका त्रिखा का स्वागत किया, जिन्होंने सीपीएस प्रौद्योगिकियों तक पहुँच को लोकतांत्रिक बनाने और नवाचार–आधारित विकास को बढ़ावा देने के बारे में बात की। आईआईटी रोपड़–टीआईएफ के मुख्य नवाचार अधिकारी डॉ. मुकेश केस्टवाल ने विशेष अतिथि के रूप में भाग लिया और इस पहल की सहयोगात्मक प्रकृति पर ज़ोर दिया इस समारोह में शिक्षा–उद्योग संबंधों को मज़बूत करने, संयुक्त अनुसंधान, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और नवाचार के अवसरों को सक्षम बनाने हेतु एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर भी हस्ताक्षर किए गए।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बचाव और राहत कार्यों में और तेजी लाने के निर्देश दिए

ब्यास में प्रभावित क्षेत्रों का दौरा; संकट से लोगों को बाहर निकालने के लिए राज्य सरकार की वचनबद्धता दोहराई

मनदीप कौर

ब्यास (अमृतसर), पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज बाढ़ प्रभावित जिलों के डिप्टी कमिश्नरों को राहत और बचाव कार्यों में और तेजी लाने के साथ–साथ बाढ़ के कारण डूबे हुए गांवों में फंसे परिवारों को सभी जरूरी सामग्री उपलब्ध कराने के आदेश दिए। मुख्यमंत्री ने आज बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का आकस्मिक दौरा किया, जिसके दौरान स्थानीय अधिकारियों ने उन्हें बाढ़ के कारण खड़ी फसलों, मकानों, सार्वजनिक इमारतों और पशुधन को हुए नुकसान की जानकारी दी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने अपनी सरकार की ओर से लोगों को हरसंभव सहायता का भरोसा दिलाते हुए कहा कि राज्य सरकार पहले ही बड़े पैमाने पर राहत और बचाव कार्य शुरू कर चुकी है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार इस संकट की घड़ी में लोगों को बाहर निकालने के लिए वचनबद्ध है और इसमें कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि डिप्टी कमिश्नरों को पंजाब के बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत और निकासी कार्य युद्धस्तर पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार बाढ़ प्रभावित जिलों में लोगों की निकासी के लिए वचनबद्ध है।

उन्होंने कहा कि डिप्टी कमिश्नरों को प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को निकालने और उन्हें तुरंत राहत प्रदान करने के लिए अपने सभी संसाधन जुटाने के लिए कहा गया है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि जिलों के सभी विभागों को इस संकट की घड़ी में लोगों को अधिकतम राहत देने के लिए मिल–जुलकर काम करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी डिप्टी कमिश्नरों को बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए भोजन, पेयजल, दवाइयां और अन्य सामान की आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। पशुपालन विभाग को प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं के लिए चारा और आवश्यक दवाइयां प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराने के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रभावित जिलों को राहत के लिए पहले ही फंड जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने आगे कहा कि जरूरत पड़ने पर जिलों को और फंड भी आवंटित किए जाएंगे। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इस नेक कार्य के लिए राज्य सरकार के पास फंड की कोई कमी नहीं है क्योंकि सरकार लोगों को राहत प्रदान करने के लिए पूरे जोश से काम कर रही है।

ाज्य में बाढ़ के कारण पैदा हुई स्थिति से निपटने के लिए परिवारों को हरसंभव सहायता देने की अपनी वचनबद्धता दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वे राहत, बचाव और निकासी कार्यों की व्यक्तिगत रूप से निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तटबंधों की दरारों को दुरुस्त करने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास किए जा रहे हैं और प्रभावित क्षेत्रों से पानी की निकासी जल्द से जल्द सुनिश्चित की जा रही है ताकि लोगों को राहत मिल सके। भगवंत सिंह मान ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग को बाढ़ प्रभावित जिलों में पानी से फैलने वाली बीमारियों को रोकने के लिए दवाइयों का पर्याप्त भंडार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पशुपालन विभाग को प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं के लिए दवाइयों और चारे की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि पानी का स्तर घटते ही विशेष गिरदावरी की जाएगी ताकि प्रभावित लोगों को उचित मुआवज़ा सुनिश्चित किया जा सके। भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार बाढ़ के कारण हुए प्रत्येक नुकसान की भरपाई करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मानव जीवन सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए लोगों की सुरक्षा के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार इस बात के लिए वचनबद्ध है कि लोगों को किसी भी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। बाढ़ प्रभावित इलाकों से लोगों को निकालने के लिए राज्य सरकार की दृढ़ वचनबद्धता दोहराते हुए, भगवंत सिंह मान ने कहा कि वे प्राकृतिक आपदा के कारण बनी स्थिति की नियमित निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस मुसीबत की घड़ी में लोगों के साथ खड़ी है और उन्हें हरसंभव सहायता प्रदान की जा रही है।

मुख्यमंत्री की ओर से पंजाब सरकार का हेलीकॉप्टर बचाव व राहत कार्यों के लिए तैनात, कैबिनेट साथियों के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा

पहली बार प्रभावित क्षेत्रों में लोगों का हेलीकॉप्टर, लोगों की सेवा के लिए लगाया, मुख्यमंत्री की ओर से गुरदासपुर जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का तूफानी दौरा

गुरदासपुर (सोनू, रविंदर)–पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फंसे परिवारों को राहत सामग्री पहुंचाने और लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए राज्य सरकार के हेलीकॉप्टर को तैनात करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा, लोगों ने हमारे पक्ष में बड़ा जनादेश देकर हमें यह हेलीकॉप्टर दिया है और संकट की इस घड़ी में लोगों की सेवा के लिए यह हेलीकॉप्टर तैनात रहेगा। आज गुरदासपुर जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का तूफानी दौरा करने के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ लोग पानी से घिरे गांवों में फंसे हुए हैं, जिन्हें तत्काल मदद की जरूरत है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों में फंसे लोगों को तुरंत सुरक्षित निकालने के लिए राज्य सरकार ने अपना हेलीकॉप्टर लोगों की सेवा में लगा दिया है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि अब से वे कार के जरिए बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे, जबकि हेलीकॉप्टर लोगों की सेवा के लिए उपलब्ध रहेगा। इस दौरान लोगों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सभी जिलों में कंट्रोल रूम स्थापित किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि भारी बारिश से हुए नुकसान की भरपाई के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि वे स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए हैं और विभिन्न जिलों के प्रशासन से पानी के स्तर और राहत कार्यों के बारे में पल–पल की जानकारी ले रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार संकट की इस घड़ी में लोगों की मदद करना अपना कर्तव्य समझती है और इस नेक कार्य के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों के दूर–दराज के इलाकों में प्रत्येक व्यक्ति तक मदद पहुंचाई जा रही है। विशेष रूप से सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में राहत सुनिश्चित करने पर जोर दिया जा रहा है ताकि लोगों को किसी भी तरह की परेशानी न हो। भगवंत सिंह मान ने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बचाव और राहत कार्यों को सबसे अधिक प्राथमिकता दी जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सभी कैबिनेट मंत्री, विधायक और अधिकारी अपने–अपने क्षेत्रों में इस मुश्किल घड़ी में जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि पानी के बढ़ते स्तर से लोगों की जान–माल की सुरक्षा के लिए उचित व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि इन जिलों के डिप्टी कमिश्नरों और एसएसपी को राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि लोगों को मदद मिल सके।

भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार भारी बारिश के कारण उत्पन्न इस स्थिति में लोगों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि मंत्री, विधायक और अधिकारी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं ताकि लोगों को इन क्षेत्रों से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पहले से ही बड़े पैमाने पर राहत और बचाव कार्य चल रहे हैं ताकि लोगों को किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार इस मुश्किल समय में लोगों की भलाई के लिए प्रतिबद्ध है।

पंजाब सरकार ने जलवायु अनुकूल और टिकाऊ बागवानी पर टेक्नोलॉजी एक्सचेंज वर्कशॉप की मेज़बानी की

जेआईसीए प्रतिनिधिमंडल ने बागवानी मंत्री मोहिंदर भगत से पीसीआरईएसएचपी के अंतर्गत सहयोग पर की चर्चा

सोनू

चंडीगढ़, मुख्यमंत्री स भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार बागवानी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए ठोस कदम उठा रही है। इसी दिशा में, पंजाब और जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) ने संयुक्त रूप से पंजाब में जलवायु अनुकूल और पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ बागवानी (पीसीआर ईएसएचपी) को बढ़ावा देने विषय पर भागीदारों के साथ नई तकनीक के आदान–प्रदान पर एक वर्कशॉप का आयोजन किया। यह कार्यक्रम कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई) परिसर, सेक्टर–31, चंडीगढ़ में हुआ। इस अवसर पर बागवानी मंत्री श्री मोहिंदर भगत ने जेआईसीए प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया, जिसमें फर्स्ट सेक्रेटरी (खाद्य एवं कृषि) श्री हेयासे ताकेहीको, जेआईसीए

इंडिया के वरिष्ठ प्रतिनिधि श्री ईजी वाकामात्सु, सर्वे टीम लीडर श्री शिनोहारा टोगो और विकास विशेषज्ञ श्रीमती निष्ठा वेंगुर्लेकर शामिल थे। सीआईआई चंडीगढ़ के चेयरपर्सन श्री अमित जैन भी उपस्थित रहे। मंत्री ने तकनीक हस्तांतरण और नवीन अभ्यासों के माध्यम से पंजाब की बागवानी को और सशक्त बनाने में सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। 30 सदस्यीय जेआईसीए दल ने मंत्री श्री मोहिंदर भगत से मुलाकात कर पंजाब फसली अवशेष प्रबंधन और टिकाऊ बागवानी परियोजना (पीसीआरईएसएचपी) के अंतर्गत साझेदारी पर चर्चा की। इसमें फसली विविधता, टिकाऊ संसाधन प्रबंधन और किसानों के हित में उन्नत तकनीक के उपयोग पर विचार–विमर्श हुआ। श्री मोहिंदर भगत ने कहा कि पंजाब की बागवानी वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना रही है और सरकार किसानों को आधुनिक तकनीक तथा अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञता प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने कहा, 卐जेआईसीए के सहयोग से पंजाब का लक्ष्य फसली विविधता को प्रोत्साहित करना, लागत कम करना और किसानों की आय बढ़ाना है।卐 फर्स्ट सेक्रेटरी श्री हेयासे ताकेहीको ने कहा कि पंजाब की बागवानी में अपार संभावनाएं हैं और जापान किसानों को लाभान्वित करने हेतु तकनीक, प्रशिक्षण और टिकाऊ पद्धतियों से सहयोग देगा। वर्कशॉप के दौरान कई सत्र आयोजित हुए जिनमें नियंत्रित वातावरण बागवानी, कृषि–तकनीक आधारित समाधान, कम–कार्बन बागवानी तथा भारत–जापान के बीच अकादमिक सहयोग जैसे विषय शामिल थे। इन सत्रों ने विशेषज्ञों को प्रस्तुति, संवाद और विचार–विमर्श का मंच प्रदान किया।

भाजपा कैंप पर पुलिस का हमला - डॉ. सुभाष शर्मा समेत कई कार्यकर्ता गिरफ्तार

मान सरकार की जमीन खिसक चुकी है, भाजपा से डर रही है: डॉ. सुभाष शर्मा, गैंगस्टरवाद और नशे को छोड़ भाजपा कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई- डॉ. सुभाष शर्मा

एसके सक्सैना

चण्डीगढ़ – खरड़ विधानसभा के मुल्लापुर बाज़ार, न्यू चंडीगढ़ स्थित खेड़ा मंदिर के नज़दीक केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को लेकर लगाए गए भाजपा कैंप को पंजाब सरकार ने पुलिस बल के सहारे कुचलने की कोशिश की। इस दौरान पंजाब भाजपा के उपाध्यक्ष डॉ. सुभाष शर्मा समेत कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी का विरोध करते हुए कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाज़ी की और इसे आप सरकार की तानाशाही व गुंडागर्दी करार दिया। डॉ. शर्मा ने तीखा प्रहार करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार पूरी तरह बौखला चुकी है। राज्य भर में भाजपा कार्यकर्ताओं को गांवों में जाने से रोका जा रहा है, रास्तों पर पुलिस की नाकेबंदी कर दी गई है। उन्होंने कहा, 卐एक तरफ पंजाब गैंगस्टरों का अड्डा बनता जा रहा है, नशा खुलेआम बिक रहा है, लेकिन मान

सरकार इन गंभीर मुद्दों पर आंखें मूंदे हुए है। उल्टा, उसे भाजपा कार्यकर्ताओं के शांतिपूर्ण कैंप से डर लग रहा है।卐 डॉ. शर्मा ने पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर कटाक्ष करते हुए कहा कि मान सरकार उनके बताए 卐साम, दाम, दंड, भेद卐 के रास्ते पर चल रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भाजपा कार्यकर्ता न तो रुकने वाले हैं, न ही दबाव में झुकने वाले। पुलिस की लाठीचार्जनुमा कार्रवाई से कई कार्यकर्ता घायल भी हुए हैं। उन्होंने कहा कि आश्चर्य की बात है कि आप सरकार खुद जगह–जगह कैंप लगाती है तो उसे लोकतंत्र कहते हैं, लेकिन भाजपा जनता को योजनाओं की जानकारी दे तो उसे 'डाटा चोरी' का नाम देकर रोक दिया जाता है। यह सरकार की हताशा और भाजपा के बढ़ते जनसमर्थन का सबूत है।

साफ़ है कि मान सरकार की जमीन खिसक चुकी है और वह भाजपा की बढ़ती ताक़त से डरी हुई है

राज्य के गरीब लोगों के राशन पर डाका किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा-मोहिंदर भगत

मनदीप कौर

जालंधर, कैबिनेट मंत्री मोहिंदर भगत ने केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा पंजाब के 55 लाख ज़रूरतमंद लोगों से राशन छीनने की नापाक साजिश की कड़ी निंदा की और कहा कि भगवंत मान सरकार राज्य के गरीब लोगों के राशन पर डाका किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। आज यहां सर्किट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, कैबिनेट मंत्री ने करतारपुर से विधायक बलकार सिंह के साथ कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के आम और गरीब लोगों के अधिकारों पर डाका डाल रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पंजाब के 8 लाख राशन कार्ड काटने के आदेश के कारण राज्य के लगभग 32 लाख लोग राशन से वंचित हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने का दावा करती है जब्कि पंजाब में 55 लाख लोगों का राशन रद्द करने की साज़िश कर रही है। उन्होंने कहा कि वोट चोरी के बाद अब भाजपा ने राशन चोरी का नया हत्थकंडा अपनाया है। उन्होंने कहा कि पंजाब की आम और गरीब जनता के मुंह से रोटी छीनने की केंद्र सरकार की इस नापाक साजिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। श्री भगत ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार की गैर–भाजपा शासित राज्यों की सरकारों और लोगों के खिलाफ धक्का जमाने की नीति जगजाहिर हो गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले केंद्र की भाजपा सरकार गैर–भाजपा शासित राज्यों की सरकारों को धौंस दिखाती थी, लेकिन अब यह सरकार उन राज्यों के लोगों को भी धमकाने लगी है। पंजाब के गरीब लोगों को

केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा पंजाब के 55 लाख ज़रूरतमंद लोगों से राशन छीनने की नापाक साजिश की कड़ी निंदा की

धमकाना भी इसी नीति का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने के.वाई.सी. का बहाना बनाकर जुलाई में 23 लाख पंजाबियों का राशन बंद किया और अब 32 लाख और लोगों का राशन 30 सितम्बर से बंद करने की धमकी दी है। उन्होंने कहा कि पंजाब के 55 लाख जरूरतमंद लोगों को राशन से वंचित करने की घिनौनी साजिश रची जा रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र का यह फैसला पंजाब विरोधी है और इससे भाजपा सरकार का गरीब विरोधी एजेंडा भी उजागर हो गया है। उन्होंने कहा का पंजाब ने देश को अनाज में आत्म–निर्भर बनाया, अब उसी पंजाब को राशन से वंचित किया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री ने प्रधानमंत्री से अपील की कि गरीबों के हक़ के लिए शर्तों पर पुनर्विचार करे और साथ ही पंजाब के लोग भी अपील की कि बीजेपी के नेता जहां दिखें उनसे सवाल पूछे कि पंजाब के राशन कार्ड क्यों काटे जा रहे हैं। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए वचनबद्ध है और एक भी राशन कार्ड रद्द नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स.भगवंत सिंह मान पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्पष्ट कर चुके है कि आम आदमी पार्टी सरकार राज्य के गरीब लोगों के साथ खड़ी है और किसी भी परिवार को राशन से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा। श्री भगत ने कहा कि मान सरकार राज्य के लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए किसी भी आंदोलन से पीछे नहीं हटेगी। इस अवसर पर जिला योजना समिति के अध्यक्ष अमृतपाल सिंह, पंजाब राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष पवन कुमार टीनू, नगर सुधार ट्रस्ट के अध्यक्ष रमनीक सिंह रंधावा, पंजाब एग्री एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष मंगल सिंह बस्सी, आप नेता राजविंदर कौर थियाडा, दिनेश ढल्ल, प्रिंस प्रेम कुमार, पिंदर पंडोरी आदि भी उपस्थित थे।

पंजाब में पार्टी को फिर से सत्ता में लाने के लिए कांग्रेस नेताओं ने संकल्प लिया

केंद्र और राज्य की सरकारों ने पंजाब को निराश किया है–वड़िंग

रमन कुमार

होशियारपुर, पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने आज यह संकल्प लिया है कि वे यकीनी बनाएंगे कि 2027 के विधानसभा चुनावों में पार्टी राज्य में सत्ता में वापसी करे। उन्होंने सर्वसम्मति से कहा कि पार्टी आलाकमान जिसे भी मुख्यमंत्री के रूप में पेश करेगा, वह सभी को स्वीकार्य होगा। यहाँ एक पार्टी रैली को संबोधित करते हुए, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा, पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा और अन्य नेताओं ने कहा कि पंजाब को आप, भाजपा और अकाली दल जैसी पार्टियों से बचाने के लिए राज्य में कांग्रेस की सरकार बनाना बेहद ज़रूरी है। इस अवसर पर बोलते हुए, वड़िंग ने कहा कि आप सरकार ने सभी वादे तोड़कर लोगों के सपनों को चकनाचूर कर दिया है। उन्होंने कहा कि पंजाब के लोगों ने अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान जैसे आप नेताओं पर बदलाव लाने का भरोसा किया था, लेकिन उन्हें कुशासन और अराजकता ही मिली। वड़िंग ने ज़ोर देते हुए कहा कि गैंगस्टरों द्वारा लगातार फिरौती मांगने की घटनाओं के कारण पंजाब में कोई भी निवेशक निवेश करने को तैयार नहीं है, जो लोग डरे और असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब में एक भी पैसा निवेश नहीं हो रहा है और नतीजतन, यहाँ कोई रोज़गार उपलब्ध नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि पंजाब पर अब तक 4.5 लाख करोड़ रुपये का कर्ज़ चढ़ चुका है। उन्होंने खुलासा किया कि पंजाब के व्यापारी और कारोबारी राज्य में निवेश करने को तैयार नहीं हैं और वे मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में निवेश कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लुधियाना दौरे के दौरान 15,000 करोड़ रुपये का निवेश लेकर गए थे। इस बीच, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने लोगों को 300 रुपये या किसानों को सालाना 6000 रुपये देने जैसी योजनाओं पर भारतीय जनता पार्टी के जनसंपर्क कार्यक्रम पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि किसानों को किसी भत्ते की नहीं, बल्कि अपनी फसलों के लिए उचित एमएसपी की ज़रूरत है। उन्होंने भाजपा नेताओं को चुनौती दी कि वे एक भी ऐसी परियोजना बताएँ, जो भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी ने पंजाब को दी हो। उन्होंने आशंका जताई कि भाजपा सरकार फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य समाप्त कर देगी, जिससे पंजाब की कृषि–केंद्रित अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ सकता है। इस अवसर पर वड़िंग ने कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को देश भर में भाजपा द्वारा शुरू की गई %वोट चोरी% से सावधान रहने की भी चेतावनी दी। उन्होंने कांग्रेस नेताओं से मतदाता सूचियों की नियमित जाँच करने की अपील की, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बिहार की तरह उनके वोट न काटे जाएँ, जहाँ भाजपा ने 60 लाख वोट काटे हैं। इसी तरह, वड़िंग ने पंजाब की आप सरकार की %खाली सरकारी भूमि के सर्वोत्तम उपयोग% के तहत खाली सरकारी ज़मीनों को बेचने की नीति का भी कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि %लैंड पूलिंग% के ज़रिए लैंड लूट योजना% को वापस लेने के लिए मजबूर होने के बाद, अब आम आदमी पार्टी की सरकार इस योजना से राज्य को हुए भारी वित्तीय नुकसान की भरपाई के लिए %पारिवार के गहने% बेचने का एक अन्य विचार लेकर आई है। जिस पर उन्होंने कहा कि इससे यही साबित होता है कि आप सरकार पंजाब के लिए आर्थिक और वित्तीय रूप से विनाशकारी साबित हुई है व इसने राज्य को दिवालियेपन की ओर धकेल दिया है। क्योंकि आप अपने परिवार के गहने तभी बेचते हैं, जब आप अपने सारे संसाधन खत्म करके पूरी तरह दिवालिया हो जाते हैं। इस दौरान अन्य के अलावा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा, पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा, पूर्व विधायक बरिंदरमीत सिंह पाहड़ा, कुलबीर सिंह जीरा, इंदु बाला और सरबजोत सिंह साबी भी मौजूद थे।

55 लाख पंजाबियों का मुफ़्त राशन बंद करने की साजिशें रच रही है केंद्र सरकार- मुख्यमंत्री

के. वाई. सी. ना होने का बहाना बना कर 23 लाख पंजाबियों का राशन जुलाई में बंद किया

पंकज

चंडीगढ़, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत 55 लाख पंजाबियों को मुफ़्त अनाज स्कीम से वंचित रखने के फ़ैसले को पंजाब विरोधी कदम बताते हुये भारतीय जनता पार्टी की सख़्त अलोचना की। आज यहाँ पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार राज्य में कुल एक करोड़ 53 लाख राशन कार्डों में से 55 लाख लोगों को दिए जा रहे मुफ़्त राशन को बंद करने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा के. वाई. सी. की रजिस्ट्रेशन न होने बहाना बना कर जुलाई महीने में 23 लाख लोगों का मुफ़्त राशन बंद कर

दिया गया है जबकि 32 लाख और लोगों का मुफ़्त राशन 30 सितम्बर से बंद करने की धमकियां दीं गई हैं। भगवंत सिंह मान ने कहा कि केंद्र सरकार अपने मंसूबों में कभी भी सफल नहीं होगी और वह राज्य में एक भी कार्ड रद्द नहीं होने देंगे। भाजपा जनहितैषी होने के बड़े दावे करती है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ़्त अनाज की शेखियां तो मारती है जबकि पंजाब में 8 लाख 2 हज़ार 493 राशन कार्ड रद्द करने की घटिया चालें चली जा रही है। केंद्र के इस फ़ैसले से राज्य के 32 लाख लोगों को मुफ़्त राशन के हक से वंचित कर दिया जायेगा। भगवंत सिंह मान ने भाजपा को घेरते हुये कहा कि 'वोट चोरी' के बाद 'राशन चोरी' के हत्थकंडे अपनाये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुफ़्त राशन बंद करने के लिए विशेष तौर पर पंजाब को निशाना बनाया जा रहा है जबकि इतिहास इस बात का गवाह है कि पंजाब ने अनाज उत्पादन में देश को आत्म निर्भर बनाने में सबसे अधिक योगदान डाला है। मुख्यमंत्री ने राशन कार्ड रद्द करने के लिए दिए जा रहे तर्कों की कड़ी निंदा की।